▸▸वर्ष : 34 ▸▸अंक : 326 ▸▸मुंबई, सोमवार, 2 फरवरी 2026 ▸▸RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸मूल्य : 3 रुपए ▸▸epaper.dobajedopahar.com ▸▸संपादक : अरुण लाल ▸▸संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD
दो बजे दोपहर

बजट 2026-27

राहत कम रोडमैप ज्यादा

शिक्षा और रोजगार के लिए क्या हुई घोषणाएं

- 3 नए आर्युर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे।
- पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी।
- STEM संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी।
- 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी।
- नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।
- 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।

▸▸ बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज; छोटे उद्योगों, कृषि और पर्यटन पर जोर

▸▸ वित्त मंत्री ने पेश किया 53.47 लाख करोड़ का बजट

▸▸ इन्फ्रास्ट्रक्चर को 32% आवंटन, ब्याज भुगतान पर 20% खर्च

▸▸ राजकोषीय घाटा 4.3% तक ले जाने लक्ष्य

एजेंसी । नई दिल्ली

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53,47,315 करोड़ रुपये खर्च का बजट (Budget 2026) पेश किया है। पिछला बजट प्रावधान 50,65,345 करोड़ रुपये का था, जिसे संशोधित अनुमान में 1,00,503 करोड़ रुपये घटाकर 49,64,842 करोड़ रुपये किया गया है। इस तरह 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में नए बजट का आकार 7.7 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में आम लोगों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने के 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि टैक्स फाइल करने में सरलता, रेल स्पीड कॉरिडोर, आयुर्वेदिक एम्स सहित हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने का एलान किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अपने लगातार 9वें वार्षिक बजट में तात्कालिक और लोक लुभावन लाभों की जगह चुनौतीपूर्ण माहौल में दीर्घावधि में देश की आर्थिक संरचना और स्थिरता को मजबूती देने पर ज्यादा जोर दिया है, जो आज वैश्विक आर्थिक राजनीतिक अनिश्चितता की दृष्टि से भी अहम है।

जलमार्ग के लिए घोषणाएं

पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग भी शुरू होंगे।

वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी।

समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी।

आयकर दाता

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आय की गलत जानकारी देने पर 100% जुर्माना सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है।मतलब कि जितनी टैक्स चोरी की कोशिश की गई उतना ही अतिरिक्त राशि दंड के रूप में चुकानी होगी।

रक्षा बजट

अबकी बार 7,84,678 करोड़ का रक्षा बजट दिया गया है। पिछले साल 6,81,210 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। 1,71,338 करोड़ रुपये पेंशन में खर्च होंगे। सरकार ने नौसेना बेडे. के लिए 25,023 करोड़ और विमान व एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।

रेलवे

अबकी बजट में रेलवे को कुल 2,93,030 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। पूंजीगत व्यय के तहत नई लाइन और दोहरीकरण आदि पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा देश में सात नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण होगा।

खेल

केंद्र सरकार ने बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के बजट में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। पहली बार मंत्रालय का 5000 करोड़ के करीब पहुंचा है। अबकी बार मंत्रालय को कुल 4479 .88 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। पिछले साल कुल 3346 .54 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। अबकी बार 1133 .34 करोड़ की ज्यादा रकम मिली है।

कृषि

मनरेगा की जगह शुरू की गई VB-G RAM G योजना को कुल 95,692 .31 करोड़ रुपये धनराशि आवंटित की गई है। वहीं मनरेगा को 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कुल 140528 .78 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग को 130451.62 और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को 9964 .95 धनराशि मिली है।

छह स्तंभ पर केंद्रित बजट

आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण को गति

आर्थिक विकास को गति देने के लिए बायोफार्मा शक्ति, रेयर अर्थ कॉरिडोर, तीन समर्पित रासायनिक पार्क, खेल के सामानों का विनिर्माण, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 200 पुराने उद्योग समूह को पुनर्जीवित करना, सीपीएसआई में हाई-टेक टूल रूम, कंटेनटर विनिर्माण, वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण और उच्च व प्रौद्योगिकी उन्नत विनिर्माण की घोषणा।

विकास के आधारों पर सुदृढ़ीकरण

पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले टियर 2 और 3 शहरों का विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कार्बन कैप्चर उपभोग और भंडार के लिए 20 हजार करोड़ की योजना, सोलर ग्लास के विनिर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनट के आयात पर बीसीडी छूट, बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को छोड़ना और सात हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे अहम ऐलान।

जन-केंद्रित विकास

बजट में जनहित से जुड़ी सुविधाओं और उनके विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना, रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना, सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, स्वयं सहायता उद्यमिता (एसएचई) की स्थापना करना और बुजुर्गों की देखभाल सेवा के लिए 1.5 लाख बहुकुल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जैसे अहम कार्यक्रमों की घोषणा।

विश्वास आधारित शासन

सीमा शुल्क पर बाध्यकारी उन्नत नियमन की वैधता को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया। कस्टम वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क का वेयरहाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली में रूपांतरण करना और भरोसेमंद आयातकों द्वारा दर्ज बिल की फाइलिंग और सामानों के आगमन को स्वचालित रूप से सूचित करने की सुविधा प्रदान किया जाएगा। वहीं, भरोसेमंद लंबी आपूर्ति चेन वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्य किया जाएगा, जिससे आयातकों के लिए कार्गो के हर बार सत्यापन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

व्यापार तथा जीवन सुगमता

विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को घटाकर दो फीसदी किया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। इसी तरह से व्यापार सुगमता लाने के लिए कई जरूरी प्रावधानों को हटाया गया है या फिर उत्पाद एवं सेवा पर लगने वाले शुल्क को हटाया या कम किया गया है।

राजकोषीय मामले 16वें वित्त आयोग के अनुरूप

राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण, शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन में मदद मिल सकेगी। कर्ज- जीडीपी अनुपात घटाकर 55 .6% पर लाने का प्रस्ताव है जो चालू वित्त वर्ष में 56 .1% है।

शेयर मार्केट और निवेशकों के लिए बड़े एलान

- दुरुपयोग रोकने के लिए देना पड़ेगा अतिरिक्त बायबैक कर।
- सभी शेयरधारकों के बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर का प्रस्ताव।
- कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए 22 प्रतिशत टैक्सेशन।
- गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए 30 प्रतिशत टैक्स।
- वायदा सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया।
- ऑप्शन प्रीमियम और कार्यकलाप पर STT को बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किया।

किस मंत्रालय को कितना बजट मिला?

- परमाणु ऊर्जा विभाग- 24123
- आयुष मंत्रालय- 4408.93
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 177061
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय- 2102.87
- कोयला मंत्रालय- 3635
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय- 17843.90
- संचार मंत्रालय- 102267
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय- 6812
- शिक्षा मंत्रालय- 139289
- विदेश मंत्रालय- 22118.97
- वित्त मंत्रालय- 1972509
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय- 106530
- गृह मंत्रालय- 255233
- जल शक्ति मंत्रालय- 94807
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- 309875.30

प्रमुख मदों में व्यय

- परिवहन- 5,98,520
- रक्षा- 5,94,585
- ग्रामीण विकास- 2,73,108
- गृह कार्य- 2,55,234
- कृषि और संबद्ध कार्यकलाप- 1,62,671
- शिक्षा- 1,39,289
- ऊर्जा- 1,09,029
- स्वास्थ्य- 1,04.599
- शहरी विकास- 85,522
- आईटी और दूरसंचार- 74,560
- वाणिज्य और उद्योग- 70,296
- सामाजिक कल्याण- 62,362
- वैज्ञानिक विभाग- 55,756
- कर प्रशासन- 45,500
- विदेश कार्य- 22,119
- वित्त- 20,649
- पूर्वोत्तर विकास- 6,812

रक्षा बजट में क्या कुछ?

- कुल 15 फीसदी की बढ़ोतरी
- 78 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित
- आधुनिकीकरण के लिए 21 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे
- रक्षा मंत्रालय (सिविल) का बजट घटकर 28,554 .61 करोड़
- रक्षा सेवाओं (राजस्व) का बजट बढ़कर 3,65,478 .98 करोड़
- रक्षा पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक 21.84% की बढ़ोतरी
- रक्षा पेंशन का आवंटन 6 .53% बढ़कर 1,71,338 .22 करोड़

एमएसएमई

200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना का प्रस्ताव।

एमएसएमई को चैंपियन के तौर पर विकसित करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव, त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव।

आत्मनिर्भर भारत निधि में दो हजार करोड़ रुपये के टॉप अप का प्रस्ताव।

TReDS के साथ एमएसएमई को सात लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि मुहैया कराई गई। TReDS के लेनदेन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य किया गया। TReDS प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट के लिए सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता।

एमएसएमई में सरकारी खरीद के बारे में सूचना साझा करने के लिए जेम को TReDS से जोड़ा गया। TReDS प्राप्तियों को अस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू किया गया।

टियर-2 और टियर-3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्रों को तैयार करने के लिए पेशेवर संस्थानों को मदद।

अर्ध पेशेवर एमएसएमई को किफायती लागतर पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता।

कृषि- किसानों के लिए योजनाएं

- कृषि मंत्रालय के लिए 1.40 लाख करोड़ से अधिक आवंटित किया गया है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस।
- बजट में छोटे व सीमांत किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, तथा तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन वैल्यू चेन को मजबूत की घोषणा।
- पशुपालन के लिए लोन-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे और पशुधन संगठनों को बढ़ावा।
- नारियल, काजू, कोको, चंदन, अखरोट, बादाम आदि फसलों के लिए समर्पित सहायता कार्यक्रम और वैश्विक बाजार हेतु ब्रांडिंग सहायता दी जाएगी।
- भारत-VISTAAR नामक बहुभाषी AI टूल शुरू होगा ताकि किसान बेहतर निर्णय ले सकें और उत्पादकता बढ़ा सकें।

महिलाओं के लिए एलान

▸▸ बजट में हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है।

▸▸ SHE Marts (शी मार्ट) महिलाओं के लिए समर्पित ऐसे बाजार/प्लैटफॉर्म हैं, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने का सीधा अवसर मिलेगा।

सत्ता पक्ष

"हम तेजी से बढती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है। बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी।

- नरेंद्र मोदी, पीएम

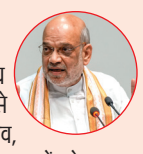

"मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से एआई तक, खेल से तीर्थ स्थलों तक विकसित भारत बजट ऐसा बजट है जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को सशक्त करता है और उन्हें साकार करने में सक्षम बनाता है।

-अमित शाह , गृह मंत्री

"अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज का बजट हमारे देश के युवाओं को समर्पित है। यह हमारे देश में महिलाओं की शक्ति को समर्पित है। और यह कर्तव्य की भावना से प्रेरित है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश में 'सबका साथ, सबका विकास' हो।

-अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री

विपक्ष

"बिना नौकरी वाले युवा। गिरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग। निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत तेजी से गिर रही है। किसान परेशान हैं। आने वाले वैश्विक झटके - सभी को नज़रअंदाज़ किया गया। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है।

-राहुल गांधी, विपक्ष के नेता

"उन्होंने बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया है। सिर्फ एक टैक्स है, जीएसटी। वे हमारा पैसा ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं। यह हमारा पैसा है। वे बंगाल से जो इकट्ठा कर रहे हैं, वह हमें पूरा फंड नहीं दे रहे हैं।

- ममता बनर्जी, प. बंगाल की मुख्यमंत्री

"अगर आप नौकरियों की बात करें, तो बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही है, खासकर पढ़े-लिखे सेक्टर में काम करने वालों को। एक चपरासी का पद, एक हेड कांस्टेबल का पद और आपको हर पद के लिए हजार से ज्यादा आवेदन मिलते हैं।

-शशि थरूर, कांग्रेस सांसद

क्या सस्ता

कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम-आयन बैटरी, और माइक्रोवेव ओवन जैसी घरेलू वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है, जिससे ये उत्पाद सस्ते होंगे। साथ ही, टीवी-शीशे, दमकल उपकरण, जूते और समुद्री खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग लागत भी कम होगी। शिक्षा और चिकित्सा के लिए 10 लाख रुपये तक का विदेशी रेमिटेंस और पर्यटन पैकेज अब कम टीसीएस (2%) के कारण अधिक किफायती हो जाएंगे। रक्षा और विमान निर्माण के पुर्जों पर छूट मिलने से 'मेक इन इंडिया' को बल मिलेगा और घरेलू स्तर पर इनका उत्पादन सस्ता होगा।

क्या महंगा

दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों में वित्तीय बोझ बढ़ना तय है। शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल पर टीसीएस दर बढ़ने से शराब महंगी होगी। इसी तरह, कबाड़, कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों पर भी कर संग्रह की दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे इनके दाम बढ़ेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए स्टॉक ऑप्शन्स और फ्यूचर ट्रेडिंग पर लेन-देन कर (STT) को 0 .02% से बढ़ाकर 0 .05% कर दिया गया है, जिससे ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। इसके अलावा, आयकर की जानकारी छिपाने या चल संपत्ति का खुलासा न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कर अनुपालन को लेकर सरकार के सख्त रुख को दर्शाता है।

कर्ज से कैसे निपटेगी सरकार?

केंद्रीय बजट में सरकार ने कर्ज को काबू में रखने की कोशिश की है, जिससे ब्याज पर कम पैसे जाएं और विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च हो सके। लक्ष्य है कि साल 2030-31 तक केंद्र सरकार का कर्ज GDP का 50 फीसदी रह जाए। साल 2025-26 में संशोधित अनुमान के मुताबिक कर्ज GDP का 56 .1% फीसदी है। 2026-27 के बजट में अनुमान जताया गया है कि कर्ज GDP का 55 .6 फीसदी तक पहुंच सकता है। यह थोड़ा कम हो रहा है।

बजट से महाराष्ट्र को एक लाख करोड़ की सौगात

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र को कुल मिलाकर लगभग एक लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 98,306 करोड़ रुपए और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित 12,355 करोड़ रुपए शामिल हैं। सीएम ने इस बजट को भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। विशेष रूप से, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए 6,103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे को नई गति देगा।

बुनियादी ढांचे और शहरीकरण पर जोर

सीएम फडणवीस ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का केंद्र का निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए बनाई गई एकीकृत शहरी विकास योजना का बड़ा लाभ महाराष्ट्र के शहरों को मिलेगा। इसके अलावा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महिलाओं के लिए समर्पित मॉल और 'लखपति दीदी' योजना के विस्तार जैसे कदम महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे।

बजट ने मुंबईकरों को किया निराश

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को खास राहत मिलती नजर नहीं आई, जिससे मुंबईकरों में निराशा है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के नागरिकों को लोकल रेल सुधार, ट्रैफिक से राहत, किफायती आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर और करों में राहत जैसी ठोस घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन बजट में मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के अलावा मुंबई लोकल से जुड़े जरूरी मुद्दों पर कोई स्पष्ट ऐलान नहीं किया गया। हालांकि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, पर रोजाना 75–80 लाख लोकल यात्रियों वाले मुंबई एमएमआर के हिस्से में क्या आएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लोकल ट्रेनों में भीड़, दुर्घटनाएं, 15 डिब्बों की लोकल और अतिरिक्त सेवाओं जैसी मांगें अनसुनी रहीं, जबकि बुलेट और हाईस्पीड रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलने से यात्री संगठनों ने चिंता जताई है कि एशिया के सबसे व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क की अनदेखी की जा रही है।

केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र के लिए प्रावधान

- 6,103 करोड़ रुपए मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए
- 1,702 करोड़ रुपए मुंबई मेट्रो के लिए प्रावधान किया
- 680 .79 करोड़ रुपए समृद्धि महामार्ग पर आईटीएस के लिए
- 646 .24 करोड़ कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना पर
- 517 .74 करोड़ रुपए पुणे मेट्रो के लिए • 462 करोड़ रुपए एमयूटीपी-3 के लिए
- 385 .78 करोड़ रुपए महाराष्ट्र टर्शरी केयर एवं मेडिकल शिक्षा विकास कार्यक्रम
- 378 .38 करोड़ रुपए महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए प्रावधान
- 313 .65 करोड़ रुपए मानव विकास के लिए कौशल एवं एप्लाइड नॉलेज परियोजना
- 283 .77 करोड़ रुपए समावेशी विकास के लिए इकोनॉमिक क्लस्टर
- 240 .90 करोड़ रुपए जिलों में संस्थागत क्षमता विकास पर
- 207 .10 करोड़ रुपए लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के सौर ऊर्जा करण हेतु
- 167 .28 करोड़ रुपए महाराष्ट्र एग्री-बिजनेस परियोजना हेतु
- 155 .32 करोड़ रुपए एमएमआर में ग्रीन मोबिलिटी के लिए

(ये आंकड़े मुंबई और पुणे क्षेत्र के प्राथमिक हैं। कुल प्रावधान : 12,355 करोड़ रुपए)

ग्रोथ हब और कनेक्टिविटी से आर्थिक उछाल

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी 5 वर्षों में ग्रोथ हब के विकास के लिए मिलने वाली निधि से मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), पुणे और नागपुर को सीधा लाभ होगा। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर, मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर राज्य की जीडीपी (GDP) में बड़ी बढ़ोतरी करेंगे, जिससे विशेष रूप से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के आर्थिक परिदृश्य में सुधार होगा। साथ ही, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास और जिला अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का विस्तार सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा।

पार्थ पवार के खिलाफ दर्ज करो मामला: अंजलि दमानिया

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के ठीक तीन दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसे लेकर राज्य की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने पुणे में प्लॉट घोटाले में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। अंजलि दमानिया का कहना है कि अजित पवार के निधन के ठीक तीन दिन बाद शपथ लेने में कुछ भी गलत नहीं है। सरकार को पुणे भूमि घोटाले की जांच नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने सरकार के सामने दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग यह है कि पार्थ पवार के खिलाफ लंबित एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। दूसरी मांग खड़गे आयोग की रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए। जब मामले की जांच चल रही हो तो पार्थ पवार को राज्यसभा का सदस्य बनाना गलत है।

लॉकअप से फरार हुआ शातिर आरोपी

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

मीरा-भाईंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस आयुक्तालय के नवघर पुलिस स्टेशन से एक शातिर आरोपी के फरार होने की घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाईंदर (पूर्व) के आजाद नगर निवासी अब्दुल मनिहार को नवघर पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी की गंभीर धाराओं के तहत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

रविवार सुबह जब पुलिस थाने के लॉकअप में साफ-सफाई का काम चल रहा था, उसी समय सुरक्षा में चूक का फायदा उठाकर अब्दुल ड्यूटी अधिकारी की आंखों के सामने से रफूचक्कर हो गया। आरोपी के लॉकअप से भागने की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस की लापरवाही और तलाशी अभियान

आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही एमबीवीवी पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आ गया। विभाग की कई विशेष टीमें गठित की गई हैं जो फरार अभियुक्त की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। हालांकि, ताजा रिपोर्ट मिलने तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस घटना ने नवघर पुलिस थाने की सुरक्षा व्यवस्था और अधिकारियों की सतर्कता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि आरोपी ने बेहद आसानी से थाने से भागने में सफलता प्राप्त की।

ठाणे स्टेशन परिसर में पैसेंजर लेने को लेकर झगड़ा

- रिक्शा ड्राइवर पर हमले के मामले में महिला ड्राइवर के खिलाफ केस

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

गावदेवी इलाके में रिक्शा स्टैंड पर सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद में एक महिला रिक्शा चालक द्वारा पुरुष चालक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना बुधवार, 28 जनवरी की शाम को गावदेवी मैदान के पास प्रणव हाउसिंग सोसायटी के सामने हुई।

वर्तकनगर निवासी रिक्शा चालक लहू टकलगे (42) अपनी बारी (नंबर) के अनुसार सवारी लेने के लिए खड़े थे। तभी रेखा (35) नामक महिला रिक्शा चालक वहां पहुंची और टकलगे के रिक्शा के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। रेखा ने टकलगे को अपशब्द कहे और जबरन अपनी गाड़ी पहले लगाने की मांग की। टकलगे द्वारा विरोध करने पर बहस बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया।

पुलिसिया कार्रवाई और जांच

घायल चालक लहू टकलगे की शिकायत पर नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में महिला रिक्शा चालक रेखा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अभय महाजन के मार्गदर्शन में पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। यह घटना स्थानीय रिक्शा चालकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सवारी लेने जैसे मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

फर्श के टुकड़े और डंडे से हमला

बहस के दौरान गुस्से में आकर महिला चालक ने पहले टकलगे को थप्पड़ मारा और फिर उन पर चप्पल फेंकी। टकलगे के अनुसार, रेखा ने सड़क किनारे पड़े फर्श (टाइल) के टुकड़े उठाकर उन पर हमला कर दिया। फर्श का एक बड़ा टुकड़ा टकलगे के सिर के पिछले हिस्से में लगा, जिससे वे लहूलुहान हो गए। इसके बाद भी महिला नहीं रुकी और पेड़ की एक लकड़ी से उनकी पीठ पर वार किया। घायल चालक को तुरंत ठाणे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनके सिर पर 3 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव पाया गया।

बकाया लेन-देन को लेकर विवाद

पैसे मांगने वाले पर चाकू और कुकर से जानलेवा हमला

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

वागले एस्टेट स्थित श्रीनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में घर के अधूरे काम के बकाया पैसे मांगने पर एक व्यक्ति पर चाकू, लोहे की छड़ और कुकर से जानलेवा हमला करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।

वागले एस्टेट के किसन नगर निवासी प्रकाश जाधव ने वारली पाड़ा के लक्ष्मण भालशंकर को अपना घर बनाने का ठेका दिया था। काम अधूरा रहने के कारण लक्ष्मण बकाया पैसे लौटाने पर सहमत हुआ था। 30 जनवरी 2026 की रात करीब 11:45 बजे जब प्रकाश जाधव अपने मित्र शिवा देवरस के साथ पैसे लेने लक्ष्मण के घर पहुंचे, तो वहां विवाद हो गया। लक्ष्मण और उसके दो अज्ञात साथियों ने अचानक हमला कर दिया। लक्ष्मण ने घर में रखे प्रेशर कुकर से प्रकाश के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए, जबकि उसके साथियों ने शिवा देवरस के साथ मारपीट की।

जानलेवा हमले और लूट का मामला दर्ज

इस मामले में शिवा देवरस की शिकायत पर श्रीनगर पुलिस स्टेशन में लक्ष्मण भालशंकर और उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ जानलेवा हमले और लूट का मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गुलजारीलाल फड़तरे के मार्गदर्शन में पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सोने की चेन छीनी गई है या हमले के दौरान कहीं गिर गई।

पीछा कर लोहे की छड़ से किया प्रहार

हमले से बचने के लिए प्रकाश और शिवा घर से बाहर भागे, लेकिन आरोपियों ने एक खेत के पास उन्हें घेर लिया। वहां एक मोटे अज्ञात आरोपी ने लोहे की छड़ से प्रकाश जाधव के माथे, भौंह और नाक पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। इसी आपाधापी में प्रकाश के गले से दो तोले की सोने की चेन भी गायब हो गई। गंभीर रूप से घायल प्रकाश जाधव किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें तुरंत ठाणे के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है।

आईआईटी बॉम्बे में सड़क निर्माण का प्रशिक्षण

बीएमसी ने किया कार्यशाला का आयोजन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

आईआईटी बॉम्बे के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. केवी कृष्णा राव ने कहा कि जमीनी स्तर पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से ही महाराष्ट्र के मुंबई की सड़कें अधिक मजबूत और टिकाऊ बन सकती हैं। डॉ. केवी मुंबई की सड़कों को अधिक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटी बी) में एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण और विचार-मंथन कार्यशाला में बोल रहे थे। इस कार्यशाला में 300 से अधिक बीएमसी इंजीनियरों ने भाग लिया। इस दौरान आईआईटी बॉम्बे के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. केवी कृष्णा राव ने कार्यशाला में तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट (थर्ड पार्टी ऑडिटिंग) के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी सहयोग और जमीनी स्तर पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से ही मुंबई की सड़कें अधिक मजबूत और टिकाऊ बन सकती हैं। इस अवसर पर बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे उप आयुक्त (इंफ्रास्ट्रक्चर) गिरीश निकम और मुख्य अभियंता (सड़क एवं परिवहन) मंतैया स्वामी भी मौजूद रहे।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुंबई में चल रहे और पूरे हो चुके सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क कार्यों की समीक्षा करना और इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और बेहतर निर्माण प्रक्रियाओं की जानकारी देना था। बीएमसी की ओर से शहर में बड़े पैमाने पर सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई जा रही हैं, ऐसे में उनकी गुणवत्ता और लंबी उम्र सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

वैज्ञानिक और व्यावहारिक जानकारी

कार्यशाला में इंजीनियरों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों की योजना, क्रियान्वयन और गुणवत्ता जांच से जुड़ी वैज्ञानिक और व्यावहारिक जानकारी दी गई। इस दौरान क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसी (क्यूएमए) और ठेकेदार कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिससे सभी संबंधित पक्षों के बीच खुली और उपयोगी चर्चा हो सकी। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने बताया कि अक्टूबर 2023 में शुरू हुई सीमेंट कंक्रीट सड़क परियोजना का लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य कई चुनौतियों के बावजूद योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 24 घंटे उड़ानें शुरू

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। अब यह हवाई अड्डा 12 घंटे के बजाय पूरे 24 घंटे संचालित होगा। आज यानी 01 फरवरी से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर चौबीसों घंटे विमान सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे पहले यह एयरपोर्ट केवल सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही कार्यरत था। बता दें कि यात्रियों के लिए इसकी शुरुआत 25 दिसंबर से की गई थी। शुरुआत में सीमित समय और सीमित उड़ानों के साथ परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन अब परिचालन समय बढ़ाए जाने से उड़ानों की संख्या में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि मुंबई महानगर क्षेत्र पर हवाई यातायात का दबाव भी कम होगा।

प्रति घंटे लगभग 10 विमानों की आवाजाही

हालांकि फिलहाल देर रात और आधी रात की उड़ानों का आधिकारिक शेड्यूल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मध्यरात्रि की सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। वर्तमान समय में नवी मुंबई एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान रात 9 बजकर 50 मिनट पर रवाना होती है, जबकि पहली उड़ान सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर संचालित की जाती है। 24 घंटे की अनुमति मिलने के बाद एयरलाइंस कंपनियां अपने स्लॉट्स धीरे-धीरे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। विमानन उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मार्च के अंत में जब एयरलाइंस का समर शेड्यूल लागू होगा, तब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। फिलहाल जहां प्रति घंटे लगभग 10 विमानों की आवाजाही हो रही है, वहीं अप्रैल महीने तक यह संख्या बढ़कर 20 प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

सिर्फ 19 दिनोंमें एक लाख यात्रियों ने किया सफर

अभी तक एयरपोर्ट पर केवल दो अतिरिक्त विमानों को शामिल किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों और हफ्तों में कई विमानन कंपनियां नवी मुंबई एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ा सकती हैं। इससे घरेलू के साथ-साथ भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रास्ते भी खुलेंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट ने 12 जनवरी को एक अहम परिचालन उपलब्धि भी हासिल की थी। एयरपोर्ट के शुरू होने के महज 19 दिनों के भीतर ही एक लाख यात्रियों ने यहां से सफर किया था, जो इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है।

देश के विमानन ढांचे को करेगा मजबूत

वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका में कई हवाई अड्डों पर रात के समय उड़ानों पर प्रतिबंध होता है। आमतौर पर शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहते हैं। इस दौरान यदि कोई यात्री फंस जाता है तो उसे टर्मिनल छोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत भारत के प्रमुख हवाई अड्डे 24 घंटे खुले रहते हैं, जिससे यात्रियों को रात के समय भी सुरक्षित स्थान उपलब्ध होता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का 24x7 संचालन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो यात्रियों की सुविधा, एयरलाइंस की क्षमता और देश के विमानन ढांचे को मजबूत करेगा।

अजित पवार विमान हादसे पर मिटकरी ने उठाए सवाल

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

एनसीपी (एपी) विधायक अमोल मिटकरी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की है। मिटकरी ने विशेष रूप से लियरजेट 45 विमान के चयन पर आपत्ति जताई है, जिसका सुरक्षा और दुर्घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने पूछा कि उपमुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए इस विमान को किन मानदंडों के आधार पर चुना गया था? साथ ही, उन्होंने पायलट सुमित कपूर की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए, जिनका पिछला रिकॉर्ड कथित तौर पर शराब के सेवन के कारण सस्पेंशन का रहा है। उन्होंने मांग की है कि पायलट की नियुक्ति के समय मेडिकल फिटनेस, फ्लाइट सेफ्टी क्लीयरेंस और क्रू मैनेजमेंट जैसे तकनीकी पहलुओं की गहन प्रशासनिक जांच की जाए।

हादसे से जुड़े रहस्य और गायब यात्री का सवाल

अमोल मिटकरी ने इस विमान हादसे से जुड़ी विसंगतियों पर भी सनसनीखेज सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि यदि हादसे में छह लोगों की मौत हुई, तो मौके से केवल पांच शव ही क्यों बरामद हुए और छठा व्यक्ति कहाँ गया? मिटकरी ने टेक-ऑफ से पहले तैयार की जाने वाली यात्रियों की डिजिटल सूची में गड़बड़ी और बार-बार पायलट बदले जाने की प्रक्रिया पर भी संदेह जताया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि दुर्घटनास्थल पर कागज का एक भी टुकड़ा जला हुआ क्यों नहीं मिला? इन सवालों के साथ उन्होंने विमान के सुरक्षा सिस्टम में संभावित समझौते की ओर इशारा करते हुए पूरी घटना की उच्च स्तरीय तकनीकी और मेडिकल जांच की मांग की है।

सत्ता पक्ष को भाया केंद्र सरकार का बजट

विपक्ष ने बताया खोखले वादों का पिटारा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जहां सत्ताधारी महायुति के नेताओं ने बजट को 'विकसित भारत' की मजबूत नींव और दूरदर्शी कदम बताया, वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी (मविआ) ने इसे खोखले वादों का पिटारा करार देते हुए 'आंकड़ों की बाजीगरी' और महाराष्ट्र की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया।

आंकड़ों की जुमलेबाजी और बेरोजगारी का संकट

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से छोटे उद्योग तबाह हो चुके हैं, लेकिन बजट में उनके लिए कोई ठोस राहत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है, फिर भी सरकार के पास रोजगार सृजन का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है।

किसानों और मध्यम वर्ग की निराशा

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह बजट महाराष्ट्र के साथ अन्याय जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले महाराष्ट्र को बजट में फिर से नजरअंदाज किया गया है। खाद की बढ़ती कीमतों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चुप्पी को उन्होंने किसानों के साथ धोखा बताया।

आर्थिक विषमता और महंगाई पर सवाल

सांसद वर्षा गायकवाड ने बजट को 'महाराष्ट्र विरोधी' करार देते हुए कहा कि राज्य के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। उन्होंने बढ़ती आर्थिक विषमता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश की बड़ी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है, लेकिन बजट में इस असमानता को कम करने का कोई उपाय नहीं है।

'अमीरों का बजट' करार

सांसद संजय राउत ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले एक दशक से बजट उद्योगपतियों और अमीर वर्ग के हित में बनाए जा रहे हैं। आम जनता, किसान और मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद रहती है, लेकिन उनके हिस्से सिर्फ घोषणाएं आती हैं। गरीबों के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है।

आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम

कौशल एवं रोजगार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि 7.4 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में अहम है। उन्होंने बताया कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना से युवाओं को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा।

नियोजित शहरीकरण का ब्लूप्रिंट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक सशक्त और निर्णायक कदम है। उन्होंने इसे नियोजित शहरीकरण का ब्लूप्रिंट बताते हुए बुनियादी ढांचे के लिए 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश और मुंबई-पुणे तथा पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर की विशेष रूप से सराहना की। फडणवीस के अनुसार, प्रत्येक 'ग्रोथ हब' के लिए प्रस्तावित 5,000 करोड़ रुपये से मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे महानगरों को नई विकास गति मिलेगी।

प्रगति को मिली नई दिशा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बजट में मुंबई और महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा क्षेत्रों में किए गए आवंटन को राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए अहम बताया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई-पुणे मेडिकल हब और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से यातायात सुलभ होगा और लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय

विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे ने बजट को 'युवा शक्ति' और 'महिला सम्मान' को समर्पित बताया। उन्होंने 'लखपती दीदी' योजना की सफलता के बाद महिलाओं के लिए स्वतंत्र मॉल (शी-मार्ट) और प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया।

औद्योगिक विकास और तकनीक को बढ़ावा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने बजट को व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख बताया। साटम ने कहा कि 'पाताल लोक' जैसी भूमिगत सुरंग परियोजनाओं के लिए टीबीएम मशीनों के स्वदेशी निर्माताओं को कर राहत देने से विदेशी निर्भरता घटेगी।

सवालों में सितारों की सुरक्षा

सलमान खान पैटर्न पर अब रोहित शेट्टी के घर पर 5 राउंड फायरिंग

विश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरी मायानगरी को दहला दिया है। शनिवार देर रात करीब 12:40 बजे अज्ञात हमलावरों ने रोहित शेट्टी के जुहू स्थित निवास 'शेट्टी टावर' पर अंधाधुंध पांच राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और रोहित शेट्टी व उनका परिवार सुरक्षित है। हमलावर ने पहले अपनी बाइक घर से कुछ दूर खड़ी की और फिर पैदल चलकर टावर तक पहुँचा और गोलियां चलाईं। वारदात से पहले उसने एक ऑटो चालक से भी बात की थी, जिसे अब पुलिस ने अहम गवाह बनाया है।

बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, दी गंभीर चेतावनी

इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग के सदस्यों—आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर और हरमन संधू—ने इसे सिर्फ एक श्ट्रेलरश करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल संदेश में रोहित शेट्टी को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा गया कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई, तो अगली बार गोलियां घर के बाहर नहीं बल्कि उनके बेडरूम के भीतर चलेंगी। संदेश में पूरे बॉलीवुड को 'लाइन पर' आने की चेतावनी भी दी गई है।

पुणे से 5 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमले के चंद घंटों बाद ही 5 आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान अमन मरोटे (27), आदित्य गायकवाड़ (19), सिद्धार्थ येनपुरे (20), समर्थ पोमाजी (18) और स्वप्निल सकट (23) के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि ये सभी आरोपी बिश्नोई गैंग के पुणे मॉड्यूल और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड शुभम लोनकर के गुर्गे हैं।

सुनील तटकरे ने विलय की खबरों को किया खारिज

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन के बाद उपजी अनिश्चितता के बीच राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने पार्टी की भविष्य की दिशा स्पष्ट कर दी है। सांसद सुनील तटकरे ने मुंबई में स्पष्ट किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा बनी रहेगी। उन्होंने शरद पवार गुट (राकांपा-शप) के साथ 12 फरवरी को होने वाले संभावित विलय की खबरों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। तटकरे ने जोर देकर कहा कि अजित पवार ने राजग के साथ जाने का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया था, और पार्टी सामूहिक रूप से उनके उस निर्णय और विचारधारा पर अडिग है।

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण और राजनीतिक स्थिरता पर सफाई

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए तटकरे ने इसे महाराष्ट्र की स्थिरता के लिए आवश्यक कदम बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार के 'विकसित महाराष्ट्र' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए यह निर्णय लेना अनिवार्य था। वहीं, विपक्ष द्वारा विलय की चर्चाओं पर हमला बोलते हुए तटकरे ने सवाल किया कि शोक की अवधि के दौरान ही ऐसी राजनीति क्यों की जा रही है? उन्होंने घोषणा की कि अजित दादा की अस्थियों को श्रद्धांजलि के लिए राज्य के सभी जिलों में ले जाया जाएगा। इस राजनीतिक हलचल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि विलय जैसी किसी भी अंतिम दौर की बातचीत की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर, शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने सनसनीखेज दावा किया कि वे पिछले तीन महीनों से गुप्त वार्ताओं का हिस्सा थे और 13 दिनों की शोक अवधि के बाद बड़े खुलासे करेंगे। तटकरे ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे केवल एक नकारात्मक धारणा बनाने की कोशिश करार दिया है।

अपने पिता की अस्थियों का कलश लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे पार्थ पवार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों के कलश रविवार को राकांपा (अजित) के पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां अस्थियों के पूजन के दौरान अजित पवार के पुत्र और युवा नेता पार्थ पवार मौजूद रहे। पार्थ जब अपने पिता के केबिन में पहुंचे और उनकी खाली कुर्सी को देखा, तो वे उसे गले लगाकर भावुक हो गए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं की आंखें भी नम हो गईं। अस्थि कलशों को राज्य के सभी जिलों में ले जाया जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता दर्शन करेंगे और बाद में स्थानीय नदियों में उनका विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान पदाधिकारी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करते नजर आए।

युवक को हिरासत में लेने वाला पुणे पुलिस आयुक्त का आदेश रद्द

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 वर्षीय रुतिक उर्फ टिक्याभाई गौतम अवधूत की याचिका स्वीकार करते हुए पुणे पुलिस आयुक्त द्वारा 6 फरवरी 2025 को जारी हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति रणजीत सिंह राजा भोंसले की पीठ ने युवक को तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का उपयोग केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना अनुचित है, जब तक कि आरोपी की गतिविधियां वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर बाधित न करें।

'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाम 'कानून और व्यवस्था' का अंतर

पीठ ने अपने फैसले में 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'कानून और व्यवस्था' के बीच सूक्ष्म अंतर को रेखांकित किया। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज शिकायतें और आरोप किसी व्यक्ति विशेष (इंडिविजुअल) के खिलाफ थे, न कि समाज या आम जनता के खिलाफ। अदालत ने उदाहरण देते हुए समझाया कि यदि कोई अपराध किसी घर की चारदीवारी के भीतर होता है, तो वह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है।

दलीलें और अदालत का निष्कर्ष

याचिकाकर्ता के वकील एम.जी. शुक्ला ने दलील दी थी कि आरोपी पर लगाए गए आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और इनसे जनजीवन की रफ्तार प्रभावित नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और कहा कि उपद्रवियों से बचने की जनता की सामान्य प्रतिक्रिया को सार्वजनिक शांति भंग करना नहीं कहा जा सकता।

मुख्यमंत्री फडणवीस जिला परिषद चुनाव प्रचार से दूर, शिंदे ने संभाली कमान

मुंबई। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव से पहले होने वाले चुनाव प्रचार से दूर रहने का निर्णय लिया है। फडणवीस ने यह फैसला अजित के निधन के कारण लिया है। अब स्थानीय नेता और पदाधिकारी ही जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में प्रचार करेंगे। फडणवीस अगले सात दिनों में राज्य के 12 जिलों में कुल 22 सभाएं करने वाले थे। राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए 7 फरवरी को मतदान होना है। इससे पहले 5 फरवरी तक प्रचार की अनुमति दी गई थी। इसी अवधि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 7 दिनों में कुल 22 चुनावी सभाएं प्रस्तावित थीं, लेकिन उन्होंने एक भी सभा न करने का फैसला लिया है। अजित पवार के निधन के कारण देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सभी चुनावी सभाएं रद्द की हैं। राज्य सरकार ने अजित पवार के निधन के बाद राज्य में तीन दिवसीय शोक की घोषणा की थी।

शिंदे ने की प्रचार की शुरुआत

वहीं, दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव प्रचार की कमान रविवार से संभाल ली है। शिंदे ने विभिन्न जिलों में प्रचार सभाओं की शुरुआत कर दी है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार शिंदे आगामी दिनों में कई जिलों का दौरा कर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।

गंभीर अपराधों के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज

8 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8.33 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति माधव जे. जामदार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता प्रणय अतुल मेहता की दलीलों को खारिज कर दिया, जो अष्टविनायक इन्वेस्टमेंट कंपनी में मैनेजर के रूप में कार्यरत था। मामले के अनुसार, 17 व्यक्तियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए विभिन्न बैंकों से 8,33,36,063 का कर्ज लिया गया और यह पूरी राशि सीधे याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। अदालत ने माना कि इतनी बड़ी रकम का खाते में आना और फिर उसका उपयोग लग्जरी कारों (दो मर्सिडीज और एक बीएमडब्ल्यू) की खरीद के लिए किया जाना, आरोपी की संलिप्तता को प्रथम दृष्टया स्पष्ट करता है।

जांच में बाधा और 'ठोस कारण' की आवश्यकता

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रिवेंटिव रिलीफ या अग्रिम जमानत का लाभ गंभीर अपराधों के आरोपियों को केवल तभी दिया जाना चाहिए जब उसके लिए कोई अत्यंत ठोस और मजबूत कारण मौजूद हो। पीठ ने सचेत किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा देने से न केवल न्याय की प्रक्रिया बाधित हो सकती है, बल्कि जांच में भी अड़चनें आ सकती हैं। अदालत के अनुसार, आरोपी बाहर रहकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या उन्हें नष्ट कर सकता है, जो आर्थिक अपराधों की गहन जांच के लिए हानिकारक है।इस मामले की शुरुआत पीड़ितों द्वारा पुणे के बंडगार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर से हुई थी।

मुलुंड से भिवंडी तक वॉटर टनल, सुधरेंगे जलापूर्ति के हालात

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई की जलापूर्ति व्यवस्था को भविष्य के लिए सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक महत्वाकांक्षी जल सुरंग परियोजना पर काम तेज कर दिया है। बीएमसी मुलुंड चेक नाका से भिवंडी के कशेली तक 7.1 किलोमीटर लंबी जल सुरंग (वॉटर टनल) का निर्माण कर रही है। सितंबर 2024 से शुरू हुई यह परियोजना अक्टूबर 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में मुलुंड नाका में 134 मीटर और कशेली में 128 मीटर गहरे शाफ्ट (गड्ढे) तैयार किए जा रहे हैं। सुरंग की खुदाई का मुख्य कार्य जुलाई 2026 से टनल बोरिंग मशीन (TBM) की सहायता से शुरू होगा। यह सुरंग न केवल पानी के वितरण को सुधारेगी, बल्कि जल रिसाव और चोरी जैसी समस्याओं को भी प्रभावी ढंग से रोकेगी।

शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान

वर्तमान में मुंबई को भातसा झील से पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनें ठाणे शहर के शहरी इलाकों से होकर गुजरती हैं। बढ़ते शहरीकरण और वहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के कारण इन पाइपलाइनों को नुकसान पहुँचने या उनमें बाधा उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। नई वॉटर टनल जमीन के काफी नीचे होने के कारण इन बाहरी बाधाओं से सुरक्षित रहेगी। बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी के अनुसार, यह परियोजना मुंबई की बढ़ती आबादी की जल मांग को पूरा करने और जलापूर्ति में स्थिरता लाने के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगी।

विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे में मुंबई का स्थान

इस परियोजना के विस्तार के साथ ही मुंबई दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जिनके पास विशाल भूमिगत जल सुरंग नेटवर्क है। लगभग 100 किलोमीटर लंबी जल सुरंगों के साथ मुंबई विश्व का दूसरा ऐसा शहर बन चुका है। आयुक्त गगरानी ने कार्यस्थल का जायजा लेते हुए बताया कि यह नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ी जलापूर्ति योजनाओं में से एक है। इस टनल के चालू होने से वितरण के दौरान होने वाली पानी की बर्बादी कम होगी और नागरिकों को अधिक दबाव के साथ स्वच्छ जल मिल सकेगा।

भाजपा को जानकारी दिए बिना राकांपा का मर्जर नहीं हो सकता : सीएम फडणवीस

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मुंबई में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जानकारी के बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों का मर्जर की बातचीत फाइनल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस तरह की कोई बातचीत हुई होती हो अजीत पवार मुझे जरुर बताते। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पत्रकारों को बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। इस समय महाराष्ट्र सहित पूरा देश सदमे में है। इस समय राकांपा के विलय की बात कुछ लोग कर रहे हैं, जो संवेदनहीनता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि राकांपा एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, लेकिन यह एनडीए के नेतृत्व वाले अलायंस का हिस्सा है और ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले सहयोगियों से सलाह लेने की उम्मीद है।

संपादकीय

बजट : उम्मीदों, संतुलन और यथार्थ का दस्तावेज

आज भारत सरकार द्वारा पेश किया गया बजट केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक सोच का प्रतिबिंब है। हर बजट की तरह इस बार भी आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसान, युवा, उद्योग और राज्यों—सभी की नजरें इस पर टिकी रहीं। सवाल वही पुराना है: क्या यह बजट विकास और समावेशन के बीच संतुलन बना पाता है? बजट का सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकार ने विकास को केंद्र में रखते हुए बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और निवेश पर जोर बनाए रखा है। सड़क, रेल, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर निवेश से रोजगार सृजन और आर्थिक गति को सहारा मिलने की उम्मीद है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार दीर्घकालीन विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही, 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भरता की दिशा में नीतिगत निरंतरता निवेशकों के लिए भरोसे का वातावरण बनाती है। मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ राहत और कुछ निराशा—दोनों भाव देखने को मिलते हैं। कर व्यवस्था में स्थिरता से करदाताओं को योजना बनाने में सुविधा मिलती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में कर राहत की अपेक्षा अधिक थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर खर्च बढ़ाने की मंशा स्वागतयोग्य है, पर इसका लाभ जमीन पर कितनी तेजी से पहुंचेगा, यही असली परीक्षा होगी। किसानों और ग्रामीण भारत के संदर्भ में बजट ने समर्थन की बात तो की है, लेकिन आय बढ़ाने के ठोस और त्वरित उपायों की कमी महसूस होती है। कृषि केवल उत्पादन नहीं, बल्कि बाजार, मूल्य स्थिरता और जोखिम प्रबंधन से जुड़ा विषय है। यदि सिंचाई, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को समग्र रूप से मजबूत किया जाए, तभी किसान वास्तव में सशक्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में सरकार का रुख संतुलित दिखता है। महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए योजनाओं का विस्तार सकारात्मक संकेत है। परंतु यह भी सच है कि बजट का प्रभाव केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि क्रियान्वयन की गुणवत्ता से तय होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निजी खर्च कम हो, इसके लिए सार्वजनिक निवेश की निरंतरता जरूरी है। वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से सरकार ने राजकोषीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है, जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। अत्यधिक कर्ज भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ बन सकता है, इसलिए इस दिशा में सावधानी सराहनीय है। हालांकि, आर्थिक सुस्ती और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मांग को प्रोत्साहित करना भी उतना ही जरूरी है—यह संतुलन साधना ही बजट की सबसे बड़ी चुनौती होती है। कुल मिलाकर, यह बजट न तो अत्यधिक लोकलुभावन है, न ही पूरी तरह कठोर। यह एक सतर्क, क्रमिक और यथार्थवादी दस्तावेज के रूप में सामने आता है। फिर भी, आम नागरिक की अपेक्षाएं पूरी तरह संतुष्ट होती नहीं दिखतीं। अब असली सवाल बजट से आगे का है—क्या घोषित नीतियां समय पर और ईमानदारी से लागू होंगी? क्योंकि अंततः बजट की सफलता भाषण में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में दिखने वाले बदलाव से मापी जाएगी।

विकसित भारत की नींव रखने वाला साहसिक बजट

डॉ.जयंतीलाल भंडारी
ख्यात अर्थशास्त्री

यकीनन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर बजट को आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर ढांचागत सुधार के साथ प्रगति करना शामिल है।

इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढ़ेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सूझबूझ पूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं।

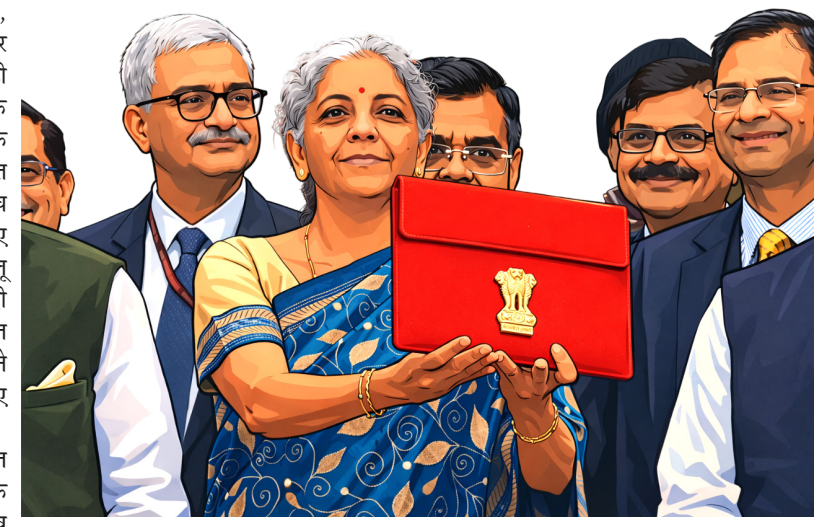

गौरतलब है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चिता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बड़े ऐलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फॉर्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेनर निर्माण, बुजुर्गों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से वित्तमंत्री इस बजट के माध्यम से युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इटेंलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए है, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। चूँकि इस समय चीन, पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश से भी देश की बाहरी सुरक्षा के खतरे बढ़े हैं, ऐसे में सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है। भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रोत्साहनमूलक प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। इतना ही नहीं अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहाँ राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए है। निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। उम्मीद करें कि इस बजट से जहाँ देश में साहसिक सुधारों का नया युग शुरू होगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निर्मित होगा। उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होगी। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

जीवन मंत्र

शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि मन, विचार और व्यवहार का संतुलन है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में इंसान बाहरी सुख-सुविधाओं से घिरा है, फिर भी भीतर अशांत है। ऐसे समय में शांति केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने की अनिवार्य शर्त बन चुकी है।

शांति : मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता

शांति की शुरुआत व्यक्ति के भीतर से होती है। जब मन स्थिर होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय विवेकपूर्ण बनते हैं। क्रोध, अहंकार और द्वेष मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं, जबकि शांति उसे मजबूत बनाती है। एक शांत व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुन पाता है। समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी शांति का महत्व उतना ही गहरा है। जहां शांति होती है, वहां संवाद पनपता है, विकास संभव होता है और संबंध मजबूत होते हैं। इतिहास गवाह है कि हिंसा ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांति को संघर्ष का सबसे प्रभावी हथियार बताया और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि बिना खून बहाए भी परिवर्तन संभव है। शांति का अर्थ अन्याय को सहना नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य के साथ उसका सामना करना है। शांत मन से किया गया विरोध अधिक प्रभावशाली और नैतिक होता है। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, तभी सच्ची शांति का निर्माण होता है। आज जरूरत है कि हम शांति को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में उतारें। परिवार में संवाद, समाज में सहिष्णुता और राष्ट्र में सद्भाव—यही शांति की सच्ची अभिव्यक्ति है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर शांति को स्थान दे, तो दुनिया स्वतः एक बेहतर और मानवीय स्थान बन सकती है। शांति : मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि मन, विचार और व्यवहार का संतुलन है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में इंसान बाहरी सुख-सुविधाओं से घिरा है, फिर भी भीतर अशांत है। ऐसे समय में शांति केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने की अनिवार्य शर्त बन चुकी है।

शख्सियत
राजकुमारी अमृत कौर

राष्ट्रहित को जीवन का लक्ष्य बनाया

राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वे कपूरथला रियासत के शाही परिवार से संबंध रखती थीं। उनके पिता राजा हरनाम सिंह कपूरथला के शासक परिवार के सदस्य थे।

राजघराने में जन्म लेने के बावजूद अमृत कौर ने विलासिता के बजाय सेवा, त्याग और राष्ट्रहित को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। अमृत कौर का बचपन अनुशासन, संस्कार और सामाजिक चेतना के वातावरण में बीता। परिवार ईसाई धर्म से जुड़ा था, लेकिन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान था। बचपन से ही उनमें गरीबों, बीमारों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देने लगी थी। शाही सुख-सुविधाओं के बीच रहते हुए भी वे आम लोगों की पीड़ा को महसूस करती थीं, जो आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करने वाली बनी। राजकुमारी अमृत कौर की प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई, इसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वहां रहकर उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और सामाजिक सेवा के ढांचे को करीब से समझा। विदेश में रहते हुए भी उनका मन भारत और उसकी समस्याओं में ही रमा रहा। शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को तार्किक, संवेदनशील और कर्मठ बनाया। भारत लौटने के बाद अमृत कौर महात्मा गांधी के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुईं। उन्होंने गांधी जी को अपना मार्गदर्शक मान लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने शाही जीवन का त्याग कर सादा जीवन अपनाया। सत्याग्रह आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद वे भारत सरकार में देश की पहली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (1947–1957) बनीं। यह जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निष्ठा और दूरदृष्टि के साथ निभाई। उनके प्रयासों से एम्स (AIIMS), नई दिल्ली जैसे विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना हुई, जो आज भी उनकी दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण है। राजकुमारी अमृत कौर का जीवन समाजसेवा को समर्पित था। वे महिलाओं, बच्चों और रोगियों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। टीबी, मलेरिया और संक्रामक रोगों के खिलाफ राष्ट्रीय कार्यक्रमों की नींव उन्हीं के कार्यकाल में पड़ी। वे रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष भी रहीं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका मानना था कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि राजकुमारी अमृत कौर का निधन 6 फरवरी 1964 को हो गया, लेकिन उनका योगदान आज भी जीवित है। एम्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां और महिला सशक्तिकरण की सोच उनके कार्यों की स्थायी विरासत हैं। वे आज की पीढ़ी के लिए इस बात का उदाहरण हैं कि जन्म चाहे शाही हो, महानता कर्मों से आती है। राजकुमारी अमृत कौर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा में त्याग, साहस और संवेदना अनिवार्य है। उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया और इतिहास में अपना नाम एक प्रेरणास्रोत के रूप में दर्ज कराया। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है जो समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है।

जीवन ऊर्जा

शकीरा का जन्म 2 फरवरी, 1977 को कोलंबिया के बैरेंक्विला में हुआ था। वे एक वैश्विक संगीत आइकन, समाजसेवी और बहुमुखी कलाकार हैं। अपनी बेली डांसिंग और 'वाका-वाका' जैसे हिट गानों से मशहूर शकीरा ने लैटिन संगीत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। कला के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में उनके मानवीय कार्यों ने उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है।

शकीरा : जन्म 2 फरवरी, 1977

जन्म

सबसे ऊंचा पेड़ भी एक छोटे से बीज से शुरू होता है

असफलता का स्वाद चखना जरूरी है, क्योंकि तभी आप जीत का असली मूल्य समझ पाते हैं। मेरी सफलता का रहस्य यह है कि मैंने कभी हार नहीं मानी, भले ही लोगों ने मेरी आवाज़ का मज़ाक उड़ाया। नियत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन याद रखें कि सबसे ऊँचा पेड़ भी एक छोटे से बीज से शुरू होता है। अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। एक महिला की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि और उसका आत्मविश्वास है। हमें दूसरों की नज़रों में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी नज़रों में खुद पर गर्व होना चाहिए। महिलाएं अब रोती नहीं हैं, महिलाएं अब सशक्त बनती हैं। अपनी खामियों को अपनाएं, क्योंकि वे ही आपको अद्वितीय बनाती हैं। कभी भी किसी को यह बताने की अनुमति न दें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। संगीत वह भाषा है जिसे पूरी दुनिया बिना किसी अनुवाद के समझ सकती है। मेरे लिए नृत्य करना केवल शरीर को हिलाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को व्यक्त करना है। मेरे पैर झूठ नहीं बोलते; वे वही महसूस करते हैं जो संगीत उन्हें महसूस कराता है। कला का उद्देश्य हमारे भीतर की धूल को साफ़ करना है। जब मैं मंच पर होती हूँ, तो मैं अपनी सारी चिंताएँ भूल जाती हूँ। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। एक बच्चे को शिक्षित करना एक पूरे राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करना है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सीखते हैं। समाजसेवा कोई काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हम सबको निभाना चाहिए। भूख का कोई धर्म नहीं होता, और शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन एक ऐसा नृत्य है जिसमें हमें गिरना और फिर से उठना सीखना होता है। प्यार वह ईंधन है जो हमें कठिन समय में भी चलते रहने की शक्ति देता है। कल की चिंता में आज की मुस्कुराहट मत खोइए।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

आस्था के दर्पण में छिपा आधुनिक विज्ञान

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥ भारतीय संस्कृति में सुबह उठकर स्नान के पश्चात उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना एक अत्यंत प्राचीन परंपरा है। बचपन से ही हमने अपने घरों में बड़ों को तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य देते देखा है। लेकिन आज की तर्कशील और आधुनिक पीढ़ी अक्सर एक सवाल पूछती है— ₹सूर्य तो हमसे करोड़ों मील दूर है, तो यहाँ जमीन पर लोटा भर पानी गिराने से उन तक पानी कैसे पहुँचेगा? क्या यह केवल पानी की बर्बादी और अंधविश्वास नहीं है? सत्य तो यह है कि हमारे पूर्वज केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक भी थे। सूर्य को जल चढ़ाना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भौतिकी (Physics) और चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) का एक अद्भुत संगम है। आइये जानते हैं इसके पीछे के तीन गहरे वैज्ञानिक सत्यों को। स्कूल में हम सबने काँच के 'प्रिज्म' के बारे में पढ़ा है, जो सफेद रोशनी को सात रंगों (VIBGYOR) में विभाजित कर देता है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस सिद्धांत को समझ लिया था। सूर्य को जल देने की एक विशेष विधि है: जल का पात्र (तांबे का लोटा) आँखों के समानांतर रखा जाता है और जल की धारा धीरे-धीरे गिराई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उस गिरती हुई जल की धारा के बीच से सूर्य को देखना होता है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

यहाँ काम करता है विज्ञान: जब सुबह की कोमल किरणें पानी की उस पतली धारा से गुजरती हैं, तो पानी एक प्राकृतिक लेंस या प्रिज्म की तरह कार्य करता है। इससे सूर्य का प्रकाश सात रंगों में टूटकर हमारी आँखों की पुतलियों पर पड़ता है। यह 'कलर थेरेपी' (Chromotherapy) का सबसे शुद्ध रूप है। ये रंगीन किरणें आँखों की नसों को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे आँखों की रोशनी तेज होती है और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है। साथ ही, ये सात रंग हमारे शरीर के सात चक्रों को संतुलित कर ऊर्जा का संचार करते हैं। अर्घ्य देने का सही समय सूर्योदय के एक घंटे के भीतर बताया गया है। इसके पीछे गहरा चिकित्सा विज्ञान है। सुबह की किरणें कोमल होती हैं और उनमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें न्यूनतम होती हैं। यह समय मानव शरीर के लिए विटामिन D के संश्लेषण हेतु सबसे उपयुक्त होता है, जो हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया हमारी 'बायोरिदम' या जैविक घड़ी को सेट करती है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मस्तिष्क में 'सेरोटोनिन' का स्तर बढ़ता है, जिससे दिनभर आलस नहीं रहता और रात में 'मेलाटोनिन' के सही स्राव के कारण गहरी नींद आती है। वेदों में इसीलिए कहा गया है'आरोग्यं भास्करामिच्छेत्', अर्थात स्वास्थ्य की कामना सूर्य से करनी चाहिए। शास्त्रों में प्लास्टिक या स्टील के बजाय हमेशा तांबे के पात्र का महत्व बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार, तांबा पानी को शुद्ध करता है। जब तांबे के संपर्क में आया ज ल सूर्य की किरणों (अग्नि तत्व) के साथ मिलता है, तो यह साधक के चारों ओर एक विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है।

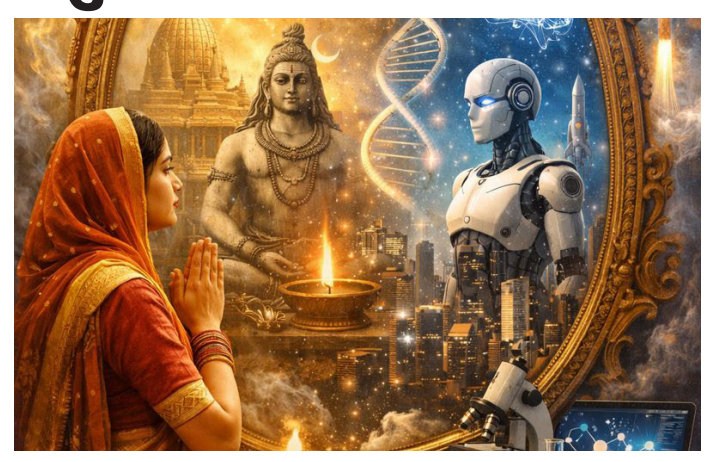

अपने विचार

हमारा निष्कर्ष साफ है यह बजट आर्थिक रणनीति की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इनमें से कितनी योजनाएं अगले साल तक भुला दी जाएंगी।

-पी. चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री

वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में पहले ही काफी तरक्की हो चुकी है, जो अब सैचुरेशन पर पहुंच गए हैं, जहां रोजाना 400 ट्रेनें चल रही हैं। यह नया कॉरिडोर बंगाल को गुजरात से जोड़ेगा।

-अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री

बजट में प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन में कटौती की गई है। उन्होंने कहा, "यह बजट दिशाहीन, दूरदृष्टिहीन, कार्रवाईहीन और जनविरोधी है। जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भी है। इस बजट में बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है।

-ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री

6 हर बार किसी हिंसक घटना के बाद इस तरह के निराधार आरोप दोहराने के बजाय पाकिस्तान को क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उसके दमन, क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघनों का इतिहास जगजाहिर है।

- रणधीर जायसवाल
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001

indiagroundreport@gmail.com

भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

इस साल का बजट प्रस्ताव एक विकसित भारत का मंत्र: संजय केलकर

ठाणेः इस साल का बजट प्रस्ताव एक विकसित भारत का मंत्र है और यह देश के विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दस वर्षों से किए जा रहे वादों के प्रति मजबूत कमिटमेंट को दर्शाता है, ऐसा मत संजय केलकर ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को न्याय देते हुए कल के भारत को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं और फंड का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में स्वदेशी की अवधारणा को मजबूत करते हुए वॉटरवे, हाईवे और रेलवे के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। केलकर ने विश्वास जताया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यह बजट भारत की तरक्की को गति देगा और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

सामूहिक विवाह सम्मेलन, 10 जोड़ों का सादगीपूर्ण विवाह संपन्न

भिवंडीः समाज में भाईचारे, सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाफिज जी ग्रुप एवं यूके ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को हफीज़ मैरिज हॉल में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 10 जोड़ों का निकाह/विवाह सादगी और विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भिवंडी पूर्व के विधायक रईस काशम शेख सहित अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, धर्मगुरु और परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजकों की ओर से नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन की आवश्यक सामग्री और उपहार भेंट कर उनके सुखद दांपत्य जीवन की कामना की गई। हाफिज जी ग्रुप के संस्थापक हाफिज अकरम खान और यूके ग्रुप के संस्थापक सलाम भाई ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे सामूहिक विवाह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का माध्यम हैं और समाज में एकता व सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं।

एक साथ विराजे जैन, देवी-देवता के कई देवी देवता

तालाबों की नगरी में बना अनूठा त्रिमंदिर

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे शहर की सांस्कृतिक विरासत में एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। 'तालाबों की नगरी' के रूप में विख्यात इस ऐतिहासिक शहर में नवनिर्मित त्रिमंदिर न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक एकता का जीवंत केंद्र बनकर उभरा है।

तीन दिवसीय प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव

पूज्य दीपक भाई के सान्निध्य में आयोजित तीन दिवसीय विशेष अनुष्ठान के साथ मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनपा आयुक्त सौरभ राव और ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय आशर सहित देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। मंत्रोच्चार और विधि-विधान के बीच पूरा परिसर भक्तिमय ऊर्जा से भर उठा, जो शहर की एकता और सभ्यता का नया प्रतीक बन गया है।

विविधता में एकता का संदेश

ठाणे शहर हमेशा से ही विविध समुदायों—हिंदू, जैन, ईसाई, मुस्लिम, पारसी और यहूदी—का घर रहा है। त्रिमंदिर की स्थापना इस शहर की सांस्कृतिक विविधता को और मजबूती प्रदान करती है। यहाँ आने वाले किसी भी संप्रदाय के भक्त को अपनेपन का अहसास होता है। यह आध्यात्मिक केंद्र आने वाली पीढ़ियों को अहिंसा, प्रेम और धार्मिक तालमेल का पाठ पढ़ाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा।

श्वेत संगमरमर का दिव्य वास्तुशिल्प

दादा भगवान फाउंडेशन और महावीर जैन ट्रस्ट के सहयोग से निर्मित यह ठाणे का सबसे बड़ा और भव्य त्रिमंदिर है। पूरी तरह से सफेद संगमरमर की नक्काशीदार शिलाओं से बना यह मंदिर अपनी दिव्यता से हर किसी को आकर्षित करता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशी विचारधारा है, जहाँ जैन और हिंदू धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं को एक ही छत के नीचे पूरी श्रद्धा के साथ प्रतिष्ठित किया गया है।

एक ही छत के नीचे देवों का समागम

त्रिमंदिर का मूल विचार 'समभाव' पर आधारित है। यहाँ श्री समंधर स्वामी (जैन तीर्थंकर) के साथ-साथ भगवान शिव, श्री कृष्ण, तिरुपति बालाजी और साईं बाबा जैसे अनेक पूजनीय देवों की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा अंबे माता, श्री गणेश, हनुमान जी और विभिन्न यक्ष-यक्षिणी देवों की विधिवत स्थापना की गई है। यह अनूठा संगम दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन गंतव्य और शांति का संदेश एक ही है।

ठाणे का नया आध्यात्मिक गौरव

समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने त्रिमंदिर को 'ठाणे का गौरव' बताया। उन्होंने कहा कि ठाणे की पहचान पहले केवल औद्योगिक और सांस्कृतिक थी, लेकिन अब यह एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। उन्होंने मंदिर निर्माण में ठाणे महानगरपालिका के सहयोग और रिकॉर्ड समय में इसके पूरा होने की सराहना की। पूज्य दीपक भाई ने इसे भारतीय सनातन संस्कृति और एकता का अनमोल उपहार करार दिया।

एमबीवीवी काशीमीरा ट्रैफिक पुलिस ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान

डीबीडी संवाददाता । मीरा रोड

मीरा रोड में स्थित वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स ने एमबीवीवी काशीमीरा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से शहर की सड़कों पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। सीएसआर के अंतर्गत यातायात पुलिस के साथ यमदूत बने कलाकारों ने दोपहिया वाहन चालकों को 250 हेलमेट वितरित किए। ज्ञात हो कि 1 से 31 जनवरी 2026 तक मनाए गए सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड ने काशीमीरा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से एक माह तक चलने वाला सड़क सुरक्षा जनजागरूकता अभियान आयोजित किया। यह पहल अस्पताल की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) योजना के तहत संचालित की गई, जिसका उद्देश्य यातायात अनुशासन को बढ़ावा देना तथा नागरिकों में सुरक्षित सड़क व्यवहार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। इस अभियान के तहत मीरा रोड एवं काशीमीरा क्षेत्र के प्रमुख यातायात चौराहों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे 250 चालकों के बीच हेलमेट वितरित किए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन, सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग तथा सड़क दुर्घटनाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई।

सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश

वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों ने दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों से प्रत्यक्ष संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों के साथ आपातकालीन एवं ट्रॉमा केयर से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बुनियादी सुरक्षा उपायों की अनदेखी किस प्रकार गंभीर सिर की चोटों और कई बार अनावश्यक मृत्यु का कारण बनती है।

यातायात पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग

उक्त अभियान को एमबीवीवी काशीमीरा ट्रैफिक पुलिस का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। एसीपी सतीश शिवरकर एवं पुलिस निरीक्षक सागर इंगोले ने अभियान को मार्गदर्शन देने और सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह जनजागरूकता अभियान समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँच सका। यातायात विभाग की सहभागिता ने सड़क सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की साझा जिम्मेदारी के संदेश को और सशक्त किया। एसीपी सतीश शिवरकर के अनुसार सड़क सुरक्षा निवारक स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिलकर हम सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। पहना गया हर हेलमेट और पालन किया गया हर यातायात नियम एक जीवन बचा सकता है।

मेरा टिकट, मेरी शान अभियान का शुभारंभ

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा रेलवे के विकास व विकसित भारत में योगदान देने की अपील

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) प्रदीप कुमार ने 1 फरवरी 2026 को चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर एक विशेष जन-जागरूकता अभियान और प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान नामक इस मुहिम का उद्देश्य यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्रियों से सीधा संवाद किया और उन्हें एक जिम्मेदार रेल यात्री बनने की शपथ दिलाई।

टिकट राजस्व का विकास में महत्व

प्रेस वार्ता के दौरान प्रदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक वैध टिकट से प्राप्त होने वाला राजस्व सीधे तौर पर रेलवे के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने में काम आता है। उन्होंने जोर दिया कि रेलवे की वित्तीय स्थिरता और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए यात्रियों का स्वैच्छिक अनुपालन अनिवार्य है। यह राजस्व क्षमता विस्तार और सेवा सुधार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ईंधन का काम करता है, जिससे अंततः यात्रियों को ही बेहतर अनुभव प्राप्त होता है।

विकसित भारत की परिकल्पना और नागरिक जिम्मेदारी

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह अभियान भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने और 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महाप्रबंधक ने आग्रह किया कि यात्री न केवल स्वयं टिकट खरीदें, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सामूहिक अनुशासन और सहयोग के माध्यम से पश्चिम रेलवे अपनी परिचालन दक्षता और सेवा उत्कृष्टता को और सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।

उड़ान-2026' का भव्य आगाज़ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

धारावी स्थित महात्मा फुले एजुकेशन ट्रस्ट के प्रांगण में शनिवार शाम को वार्षिक स्नेह सम्मेलन 'उड़ान-2026' का रंगारंग आयोजन अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। इस अवसर पर ट्रस्ट द्वारा संचालित राजे शिवाजी विद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय (सभी माध्यम) और मनोहर जोशी महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय एकता पर आधारित कव्वाली और आकर्षक नृत्य कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे, जिसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया।

ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर कलात्मक प्रहार

इस महोत्सव का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को जागरूक करना भी था। छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए नारी शक्ति, सावित्रीबाई फुले का कन्या शिक्षण और वृद्धाश्रम के बढ़ते चलन जैसे गंभीर विषयों को प्रभावी ढंग से दर्शाया। इसके अलावा, आज की पीढ़ी में बढ़ती मोबाइल की लत जैसे समसामयिक मुद्दों पर भी लघु नाटिकाओं और प्रदर्शनों के माध्यम से चोट की गई। इन प्रस्तुतियों ने न केवल छात्रों के कला-गुणों को निखारा, बल्कि उपस्थित अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया।

दिग्गज अतिथियों की उपस्थिति और पुरस्कार वितरण

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयकर अधिकारी रामकृष्ण झा और विशेष अतिथि के रूप में 'दोपहर का सामना' के उप-संपादक संदीप पांडेय सहित वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू बिडकर व नगरसेविका आशा काले उपस्थित रहीं। ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बाबूराव माने ने विद्यार्थियों की हौसलाअफजाई करते हुए वर्ष भर शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव दिलीप शिंदे, कोषाध्यक्ष प्रमोद माने और विभिन्न विभागों की प्रधानाचार्याओं सहित समस्त शिक्षकवृंद और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद थे।

मनपा सोमवार को कोपरी क्षेत्र में चलाएगी गहन सफाई अभियान

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के विजन के तहत सोमवार, 2 फरवरी को सुबह 7 बजे से नौपाड़ा प्रभाग समिति के अंतर्गत एक व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व मनोनीत महापौर शर्मिला पिंपोलकर करेंगी। अभियान की तैयारियों को लेकर रविवार, 1 फरवरी को एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रानी शिंदे और नगरसेवक भरत चव्हाण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख क्षेत्र और अभियान की रूपरेखा

यह विशेष स्वच्छता अभियान कोपरी के अष्टविनायक चौक से शुरू होकर कोपरी गांव, कन्हैया नगर, सिद्धार्थ नगर और बारा बंगला स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान केवल कचरा उठाना ही नहीं, बल्कि सड़कों को पानी से धोना, सार्वजनिक शौचालयों की गहन सफाई और कीटाणुशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे रूट पर मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। स्वच्छता के साथ-साथ इस अभियान में पर्यावरण बचाने का संदेश भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। अभियान के दौरान चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा, ताकि शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ावा मिले। मनपा प्रशासन ने इस मुहिम के माध्यम से नागरिकों से भी स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की है।

धूमधाम से मना प्रगट महोत्सव

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

मीरा रोड में हर साल की तरह इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा प्रगट महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शहर भर में कई धार्मिक आयोजन किए गए। इसी कड़ी में विश्वकर्मा समाज की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था श्री विश्वकर्मा फाउंडेशन द्वारा भाईंदर (पू.) स्थित काजल ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर भगवान विश्वकर्मा की जयंती भक्ति भाव से मनाई गई। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत विश्वकर्मा समाज कार्यालय में भगवान श्री विश्वकर्मा की कथा के साथ हुई। संध्याकाल में सम्पन्न हुई भगवान विश्वकर्मा की सामूहिक आरती में बड़ी संख्या में समाजबंधु शामिल हुए। संगीतमय भजन संध्या के दौरान भगवान विश्वकर्मा के भजनों पर भक्तगण झूम उठे और जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा।

11 वर्षों से मनाया जा रहा है प्रगट उत्सव

विश्वकर्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश विश्वकर्मा ने आयोजन को लेकर कहा कि मीरा-भाईंदर शहर में बड़ी संख्या में समाज के लोग निवास करते हैं और शहर के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी उद्देश्य से समाज को एकजुट करने के लिए विगत 11 वर्षों से भगवान का प्रगट उत्सव भक्ति भाव से मनाया जा रहा है।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

राशिफल

प्रियंका जैन

मेष योजना फलीभूत होगी। मनमाफिक स्थानांतरण या पदोन्नति हो सकती है। कार्यस्थल पर सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने की इच्छा रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। घर-परिवार की चिंता रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। दूर से अच्छी खबर मिल सकती है।

वृष डूबी हुई रकम प्राप्त होने के योग हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा। कोई बुरी खबर मिल सकती है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। दुष्टजनों से सावधानी आवश्यक है।

मिथुन ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है। भूमि व भवन आदि के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में चैन रहेगा। शत्रु पस्त होंगे। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। सभी कार्य पूर्ण होंगे।

कर्क फालतू खर्च होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। धन की तंगी होगी। बेकार बातों पर ध्यान न दें। विचारों की स्पष्टता न होने से उलझनें रहेंगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन संभव है। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

सिंह प्रियजनों के साथ बेवजह रिश्तों में खटास आ सकती है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। हताशा का अनुभव होगा। मन की बात किसी को न बतलाएं। संवेदनशीलता बढ़ेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। अपरिचित व्यक्तियों पर अंधविश्वास न करें।

कन्या पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। शैक्षणिक व शोध कार्य मनोनुकूल रहेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी। नौकरी में कोई नया कार्य कर पाएंगे। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा।

तुला नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। मेहनत का फल प्राप्त होगा। अपेक्षित कार्य समय पर पूरे होंगे। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबारी लाभ बढ़ेगा। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे।

वृश्चिक दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट से आशातीत लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। राजकीय बाधा दूर होगी। तनाव व चिंता में कमी होगी। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है।

धनु चोट व दुर्घटना से शारीरिक हानि की संभावना है। दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें। बिना वजह कहासुनी हो सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। यात्रा यथासंभव टालें। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। धैर्य रखें।

मकर राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। कोई रुका काम बन सकता है। तीर्थयात्रा की योजना बनेगी। तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

कुंभ आत्मसम्मान बना रहेगा। अच्छी खबर प्राप्त होगी। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। मान-सम्मान मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। भूले-बिसरे साथी तथा रिश्तेदारों से मुलाकात होगी।

मीन भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी। समय की अनुकूलता का लाभ लें। कारोबारी लाभ बढ़ेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। निवेश शुभ रहेगा। जल्दबाजी न करें।

मूलांक से खुलते हैं ग्रह, स्वभाव और शुभ दिन के संकेत

प्रियंका जैन
9769994439

दुनिया की हर गणना, हर हिसाब और हर संख्या केवल 0 से 9 तक के अंकों के सहारे ही खड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही साधारण से दिखने वाले अंक हमारे जीवन की दिशा, सोच, स्वभाव और भाग्य के संकेत भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। भारतीय ज्योतिष परंपरा में अंक ज्योतिष को एक महत्वपूर्ण विद्या माना गया है, जिसमें जन्म तिथि के अंकों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई रहस्यों को समझने की कोशिश की जाती है। माना जाता है कि जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, उसी दिन से कुछ विशेष ग्रहों की ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है और वही ऊर्जा आगे चलकर उसके निर्णयों, रिश्तों, सफलता और संघर्ष को प्रभावित करती है।

अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक की अवधारणा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जन्म तिथि के अंकों का योग मूलांक कहलाता है, जो व्यक्ति के स्वभाव, मानसिक प्रवृत्ति और आंतरिक ऊर्जा को दर्शाता है। वहीं जन्म तिथि, माह और वर्ष के कुल योग से बना अंक भाग्यांक कहलाता है, जो जीवन की राह, उतार-चढ़ाव और अवसरों की कहानी कहता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 माना जाता है, जबकि 11 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1+1 करके 2 बनता है। इसी तरह हर जन्म तिथि किसी न किसी अंक और ग्रह से जुड़ी होती है।

अंक ज्योतिष के अनुसार 1 से लेकर 9 तक हर अंक का संबंध किसी विशेष ग्रह से माना गया है। मूलांक 1 सूर्य ग्रह से जुड़ा होता है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ऐसे लोग स्वाभाव से नेतृत्व करने वाले, आत्मनिर्भर और अपनी पहचान बनाने की तीव्र इच्छा रखने वाले होते हैं। मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है, जो मन और भावनाओं का कारक है। इस अंक के लोग संवेदनशील, कल्पनाशील और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं। मूलांक 3 बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है, जो ज्ञान, धर्म और विस्तार का प्रतीक है, इसलिए इस अंक के जातक शिक्षित, मार्गदर्शक स्वभाव के और नैतिक मूल्यों को महत्व देने वाले होते हैं।

मूलांक 4 को राहू का अंक माना जाता है, जो अचानक परिवर्तन और रहस्य का प्रतीक है। ऐसे लोग पारंपरिक सोच से हटकर चलने वाले होते हैं और उनके जीवन में उतार-चढ़ाव अधिक देखने को मिलते हैं। मूलांक 5 बुध से जुड़ा होता है, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का ग्रह है। इस अंक के लोग तेज दिमाग वाले, संवाद में निपुण और बदलाव पसंद करने वाले होते हैं। मूलांक 6 शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले, कलाप्रिय और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। मूलांक 7 केतु से जुड़ा होता है, जो आध्यात्म और वैराग्य का संकेत देता है। इस अंक के लोग गहरे विचारों में डूबे रहने वाले, शोध और आत्मचिंतन पसंद करने वाले होते हैं। मूलांक 8 शनि ग्रह का अंक माना जाता है, जो कर्म, संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। ऐसे लोगों को जीवन में मेहनत और परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः उन्हें स्थायी सफलता मिलती है। मूलांक 9 मंगल से संबंधित है, जो साहस, ऊर्जा और पराक्रम का ग्रह है। इस अंक के लोग निडर, तेज निर्णय लेने वाले और संघर्ष से न घबराने वाले होते हैं।

आम बजट 2026-27: UP-Bihar के हिस्से में भी बहुत कुछ

UP के लिए खुला पिटारा, दो हाईस्पीड ग्रीन कारिडोर

- वाराणसी में पानी के जहाज की मरम्मत के लिए बनेगा सेंटर
- विकसित भारत की राह आसान करेगा आम बजट: मुख्यमंत्री

एजेंसी । लखनऊ/वाराणसी

केंद्र सरकार के आम बजट 2026 में यूपी के साथ-साथ वाराणसी को अहम बुनियादी सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। बजट में काशी के लिए दो हाई-स्पीड ग्रीन कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। पहला रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा. वहीं, दूसरा रेल कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बनेगा। उत्तर प्रदेश को कुल 1,500 किलोमीटर लंबाई के हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं। इसके अलावा समुद्री विमान संचालन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना और जहाज मरम्मत सुविधा की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जा रहे हैं, इसमें यूपी में पहले से पांच नदियों पर काम चल रहा है। मथुरा में नए मकानों के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में नए हॉस्टल, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण संस्थान और कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले प्रावधान शामिल हैं।

75 जिलों में ट्रामा सेंटर

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा जिला अस्पतालों की क्षमता 50 फीसदी तक बढ़ाने की बात कही गई है। विशेषज्ञों ने बजट को संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। उनका मानना है कि कर राहत, सस्ती दवाएं और बुनियादी ढांचे में निवेश से आम लोगों को लाभ मिलेगा, हालांकि रोजगार सृजन और महंगाई नियंत्रण पर और अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बनी हुई है।

ODOP को बूस्ट करेगी हैंडलूम योजना

महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के एक जिला, एक उत्पाद योजना को को फायदा मिलेगा। सूबे से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद देशभर में इसे लागू किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को अभूतपूर्व बताया। कहा, जीएसटी सुधारों के सकारात्मक परिणाम देश पहले ही देख चुका है और अब आयकर कानून को सरल बनाकर अप्रैल से लागू करने का निर्णय भी सराहनीय है। इससे अधिक लोग कर प्रणाली से जुड़ेंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय आम बजट 2026-27 को देश के भविष्य के लिए दूरदर्शी और संतुलित दस्तावेज बताते हुए इसकी खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि 145 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को समेटे हुए नए और विकसित भारत की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करता है।

नोएडा पहला सेमीकंडक्टर पार्क

देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी मिल गई है। ग्रेटर नोएडा में देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। यह पार्क ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। देश में छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। वाराणसी स्थित सारनाथ और मेरठ के पास हस्तिनापुर को प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। सारनाथ में बौद्ध विरासत पर फोकस किया जाएगा, जो पहले से ही बजट में शामिल था।

स्टेम संस्थानों की स्थापना

यूपी के प्रत्येक जनपद में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण, स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) संस्थानों की स्थापना और युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के प्रस्ताव भविष्य की पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। व्यापक सुधारों के जरिए हर क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर सृजित किए गए हैं, जिससे आम नागरिकों का जीवन अधिक सरल और सुगम होगा।

इन शहरों को 12.2 लाख करोड़

पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12 .2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा। यूपी में पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले 25 शहर हैं. इनको फायदा होगा. इन शहरों में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आर्थिक विकास को तेज करने वाला बजट है, जो युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग को नए अवसर प्रदान करेगा।

औपनिवेशिक काल में बंगाल था मुख्य केंद्र बिंदु: डेन मॉरिश

एजेंसी । वाराणसी

ताज गंगेज होटल में आयोजित काशी साहित्य कला उत्सव के चौथे संस्करण के तीसरे दिन रविवार को साहित्य प्रेमियों को इतिहास और कल्पना के संगम से रूबरू होने का अवसर मिला। इस अवसर पर चर्चित लेखक डेन मॉरिश ने अपनी बहुचर्चित कृति "द पॉइज़नर ऑफ़ बंगाल" पर आधारित संवाद सत्र में औपनिवेशिक भारत की सामाजिक, प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। डेन मॉरिश ने बताया कि उनका उपन्यास दो भाइयों के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां सत्ता, भय और बीमारी की पृष्ठभूमि में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। कथा उस दौर को उजागर करती है, जब प्लेग जैसी महामारी ने समाज को झकझोर दिया था और प्रशासनिक तंत्र चुनौतियों से जूझ रहा था। लेखक ने कहा कि कहानी केवल एक अपराध कथा नहीं, बल्कि उस समय के सामाजिक तनाव और मानवीय त्रासदी का दस्तावेज है।

- काशी साहित्य कला उत्सव में औपनिवेशिक इतिहास और रहस्य साहित्य पर मंथन

दस्तावेजों ने उपन्यास को बनाया प्रामाणिक

बंगाल को कथा का केंद्र बनाने के पीछे कारण स्पष्ट करते हुए डेन मॉरिश ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के कालखंड में बंगाल प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेख, सरकारी दस्तावेज और वास्तविक घटनाएं उनके शोध का आधार बनीं, जिससे उपन्यास को प्रामाणिकता मिली। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास इतिहास को नए नजरिये और गहन शोध के साथ प्रस्तुत करने का रहा है। भारत में वैक्सीन और स्वास्थ्य व्यवस्था के विकास पर बोलते हुए लेखक ने कहा कि उस समय संसाधनों की कमी, तकनीकी सीमाएं और आंतरिक चुनौतियां स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार में बड़ी बाधा थीं। उन्होंने युवा लेखकों को सलाह दी कि वे लेखन से पहले विश्वसनीय और पारंपरिक स्रोतों से गंभीर शोध अवश्य करें। अपने शोध अनुभव साझा करते हुए डेन मॉरिश ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्रालय की फाइलों, पुलिस अभिलेखों, क्षेत्रीय समाचार पत्रों और स्थानीय लोगों से हुई बातचीत को आधार बनाया।

लाजिस्टिक हब बनेगा बिहार कम होगा भाड़ा

- गंगा, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन नदियों का जल नेटवर्क होगा मजबूत

एजेंसी । पटना

आम बजट में बिहार के हिस्से में भी बहुत कुछ आया है। बिहार को बुनियादी ढांचे में जल मार्ग, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी जैसी सौगात मिली है। सरकार का पूरा फोकस माल ढुलाई को कम करना है, इसके लिए राज्य को लाजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। वाराणसी की ही तरह पटना में भी इनलैंड वाटरेज को मजबूत करना है। अब गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और कार्गो वेसल्स की मरम्मत और तकनीकी सेवाओं के लिए पटना में ही उच्चस्तरीय सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पटना और वाराणसी के साथ-साथ गंगा, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन जैसी नदियों के जल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत बिहार के प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हास्टल बनाने का प्रोग्राम है। इसके अलावा बजट में पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। इससे बिहार को औद्योगिक निवेश, आधारभूत ढांचे के विस्तार और रोजगार के क्षेत्र में सीधा लाभ मिलेगा। शहरी विकास से जुड़े प्रावधान राज्य के शहरों को आधुनिक स्वरूप देने में सहायक होंगे।

दीर्घकालीन विकास की आधारशिला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट 2026 को देश के दीर्घकालीन विकास की मजबूत आधारशिला बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट सकारात्मक सोच के साथ तैयार किया गया है और विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखकर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश को सीधा लाभ

- तेज रेल कनेक्टिविटी वाराणसी से हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से यात्रा समय घटेगा और व्यापार बढ़ेगा
- रोजगार के नए अवसर AI सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं को नौकरी
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर जिले में ट्रॉमा/इमरजेंसी सेंटर से इलाज तुरंत मिलेगा, जानें बचेंगी
- महिला शिक्षा को बढ़ावा हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों की पढ़ाई आसान होगी
- आर्थिक गतिविधियों में तेजी जहाज मरम्मत केंद्र और लॉजिस्टिक्स से उद्योगों को फायदा

बिहार को सीधा लाभ

- नए उद्योग और रोजगार शिप रिपेयर व जलमार्ग आधारित इकोसिस्टम से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा
- व्यापार और लॉजिस्टिक्स मजबूत गंगा जलमार्ग से माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी
- राज्य की अर्थव्यवस्था को बल बुनियादी ढांचे में निवेश से विकास की रफ्तार बढ़ेगी
- युवाओं को काम के अवसर तकनीकी व सहायक सेवाओं में नई नौकरियां

नीतीश ने एक्स पर शेयर की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि बजट में घोषित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर देश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देंगे। इनमें वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास की घोषणा से आंतरिक जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना से बिहार के उद्योग, व्यापार और निर्यात गतिविधियों को मजबूती मिलेगा।

व्यापार जगत

बजट से निवेशकों को झटका, नहीं मिली राहत

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्रीय बजट के साथ ही घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त दबाव देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ाने की घोषणा ने बाजार की धारणा को झकझोर दिया। निवेशकों को जहां टैक्स में राहत की उम्मीद थी, वहीं उलटे फैसले ने बाजार में बिकवाली की तेज लहर पैदा कर दी। बजट प्रस्तावों के अनुसार फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी की दर 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि ऑप्शंस पर यह टैक्स 0.10 प्रतिशत से बढ़कर 0.15 प्रतिशत हो गया। लंबे समय से एसटीटी में कटौती की मांग कर रहे बाजार सहभागियों के लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हुआ, जिससे कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ गया।

- बजट की घोषणा से शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल
- एसटीसी में कटौती की मांग कर रहे निवेशकों में चिंता

29 शेयर्स में गिरावट, 26 लाल निशान में बंद

नकारात्मक माहौल का असर प्रमुख सूचकांकों पर साफ दिखाई दिया। एक समय सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर गिरावट में चले गए थे। दिन के अंत में हालांकि मामूली सुधार जरूर दिखा, लेकिन इसके बावजूद 26 शेयर लाल निशान में बंद हुए और केवल चार शेयरों में ही तेजी टिक सकी। निफ्टी की स्थिति भी इससे अलग नहीं रही—शुरुआती दबाव के बाद भी 50 में से 43 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

आईटी सेक्टर में राहत, चार फीसद का उछाल

हालांकि बाजार की इस उथल-पुथल के बीच आईटी सेक्टर ने राहत की सांस ली। शेयर बायबैक के टैक्सेशन में बदलाव से आईटी कंपनियों में खरीदारी लौटी, जिससे आईटी इंडेक्स दिन के निचले स्तर से लगभग 4 प्रतिशत तक उछल गया। विप्रो के शेयर 2 .07 प्रतिशत और टीसीएस के शेयर 2 .02 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स उच्चतम स्तर से 2873.23 अंक गिरा

इंट्रा-डे कारोबार में सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से 2,873 .23 अंक तक फिसल गया, जबकि निफ्टी में 869 .15 अंकों की तेज गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट बाजार में फैले भय और अनिश्चितता का साफ संकेत मानी जा रही है। सेक्टोरल स्तर पर देखें तो आईटी और टेक सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सूचकांक भारी बिकवाली की चपेट में रहे। पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मेटल इंडेक्स 3 .85 प्रतिशत टूट गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भी 2 से 3 प्रतिशत तक की कमजोरी देखने को मिली।

UPI ने रचा नया कीर्तिमान, जनवरी में 21.70 अरब का लेनदेन

एजेंसी । नई दिल्ली

देश की डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनवरी माह में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से हुए लेन-देन ने अब तक का सर्वोच्च स्तर छू लिया। इस दौरान कुल 21.70 अरब लेन-देन के जरिये 28.33 लाख करोड़ रुपये का भुगतान दर्ज किया गया, जो डिजिटल लेन-देन में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

एनपीसीआई ने जारी किया आंकड़ा

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में यूपीआई लेन-देन का कुल मूल्य 27 .97 लाख करोड़ रुपये रहा था। इसके मुकाबले जनवरी में लेन-देन के मूल्य में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला। मासिक आधार पर इसमें लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी महीने में प्रतिदिन औसतन करीब 70 करोड़ यूपीआई लेन-देन हुए। इनका दैनिक औसत मूल्य लगभग 91,403 करोड़ रुपये रहा, जो देशभर में डिजिटल भुगतान के व्यापक विस्तार की ओर इशारा करता है।

सालाना 28 फीसद की हो रही बढ़ोत्तरी

डिजिटल भुगतान क्षेत्र की इस तेज़ बढ़त पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्ल्डलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमेश नरसिम्हन ने कहा कि यूपीआई की विकास दर लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार, जनवरी में किए गए 21.7 अरब लेन-देन न केवल दिसंबर से अधिक रहे, बल्कि सालाना आधार पर लगभग 28 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को भी दर्शाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरल प्रक्रिया, तेज़ ट्रांजैक्शन और व्यापक स्वीकार्यता के कारण यूपीआई देश की भुगतान प्रणाली की रीढ़ बनता जा रहा है, और आने वाले महीनों में इसके नए रिकॉर्ड बनने की संभावना बनी हुई है।

महंगा हो गया कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने फरवरी की शुरुआत के साथ ही 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में वृद्धि कर दी है, जबकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब है कि घरेलू बजट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आईओसीएल की जानकारी के अनुसार, दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1,740.50 रुपये में उपलब्ध होगा, जो पहले 1,691.50 रुपये में बिकता था। कोलकाता में यह सिलेंडर अब 1,844.50 रुपये का हो गया है, जबकि जनवरी में इसकी कीमत 1,795 रुपये थी। मुंबई में 19 किलो सिलेंडर के दाम 1,692 रुपये तक बढ़ाए गए हैं, और चेन्नई में यह अब 1,899.50 रुपये हो गया है।

- घरेलू कनेक्शन की दर में कोई बदलाव नहीं

घरेलू सिलेंडर 853 रुपये का

वहीं, 14 .2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर है। दिल्ली में इसका रेट 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852 .50 रुपये और चेन्नई में 868 .50 रुपये है। अन्य शहरों जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी और पटना में भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। घरेलू सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदलाव किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत और टैक्स संरचना के आधार पर तय की जाती है। जनवरी में प्राकृतिक गैस की कीमत में बढ़ोतरी के कारण फरवरी में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हर महीने की पहली तारीख को ओएमसी इस लागत की समीक्षा करके नए रेट घोषित करती हैं।

GST संग्रह में इजाफा, आयात से बढ़ी कमाई

6.2 फीसद की बढ़ोत्तरी के साथ 1.93 लाख करोड़ रुपये की आय

नई दिल्ली। सरकारी वित्तीय मोर्चे पर राहत देने वाले संकेत सामने आए हैं। जनवरी महीने में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल कर प्राप्ति 1.93 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई। आयात से प्राप्त राजस्व में आई तेज़ बढ़ोतरी इस वृद्धि का प्रमुख आधार बनी। जीएसटी महानिदेशालय द्वारा रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह भी बेहतर रहा। इसमें 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी अवधि में करदाताओं को दिए गए कुल रिफंड में 3.1 प्रतिशत की कमी आई, जो 22,665 करोड़ रुपये पर सिमट गया।

घरेलू बाजार से आए 1.41 लाख करोड़

विस्तृत आंकड़ों पर नजर डालें तो घरेलू बाजार से प्राप्त जीएसटी राजस्व जनवरी में 4 .8 प्रतिशत बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं आयात से होने वाली कर वसूली में 10 .1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 52,253 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस दौरान तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों से उपकर के रूप में 5,768 करोड़ रुपये की वसूली की गई। तुलनात्मक रूप से देखें तो जनवरी 2025 में उपकर संग्रह 13,009 करोड़ रुपये रहा था, जब कारों और तंबाकू जैसे विलासिता, हानिकारक और अहितकर उत्पादों पर भी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता था। बाद में नीति में बदलाव के तहत अब यह उपकर केवल तंबाकू एवं उससे संबंधित वस्तुओं तक सीमित कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की थी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली और कई वस्तुएं सस्ती हुईं। हालांकि, दरों में इस कमी का असर कर संग्रह पर भी पड़ा है। इसके बावजूद जनवरी के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि आर्थिक गतिविधियों और आयात में तेजी से राजस्व में संतुलन बना हुआ है।

खेल बजट 2026

खिलाड़ियों पर सरकार मेहरबान

- खेल मंत्रालय को मिला अभी तक का सबसे बड़ा बजट, 4479 .88 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटन
- पिछली बार की तुलना में खेल बजट में 1133 करोड़ रुपये की वृद्धि
- खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को पहली बार 500 करोड़ रुपये का आवंटन

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया। इसमें युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई, जिसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है। पहली बार उन्हें 500 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.88 करोड़ रुपये है जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपये से 1133.34 करोड़ रुपये अधिक है।

साइ को मिला फायदा, डोपिंग एजेंसियों के बजट में कटौती

राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए आवंटित राशि को 880 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 917 .38 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देशभर के स्टेडियमों के रखरखाव और उनके उपयोग की जिम्मेदारी भी साइ की होती है। हालांकि, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी एजेंसी का बजट क्रमशः 28 .55 करोड़ रुपये से घटाकर 23 करोड़ रुपये और 24 .30 करोड़ रुपये से घटाकर 20 .30 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

खेलो इंडिया को मिली इतनी राशि

सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 924 .35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके लिए पिछले वर्ष आवंटित राशि 1000 करोड़ रुपये थी, लेकिन अंतिम व्यय 700 करोड़ रुपये रहा। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि इस वर्ष 28 .05 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है। राष्ट्रमंडल खेल इस वर्ष जुलाई-अगस्त में ग्लासगो में होंगे।

खेल बजट की अन्य घोषणाएं

- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के लिए आवंटित बजट भी 78 .64 करोड़ रुपये से घटाकर 46 .98 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान राशि को तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- सरकार ने इस वर्ष खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 28 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया है।
- राष्ट्रीय खेल संघों के लिए सहायता राशि में भी मामूली वृद्धि की गई है, जो 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 425 करोड़ रुपये हो गई है।
- युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की धनराशि इस वर्ष 57 .68 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 58 .41 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- युवा हॉस्टलों के आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यह पिछले साल के 1 .10 करोड़ रुपये की तुलना में इस साल 19 .20 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना में भी भारी वृद्धि की गई है। इसे पिछले वर्ष के 275 .00 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 357 .39 करोड़ रुपये मिलेंगे।

खेल सामग्री उद्योग को बढ़ावा

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती खेल सामग्री के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की भारत की क्षमता पर जोर दिया और इस तरह से खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'मैं खेल सामग्री के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूं जिससे उपकरण डिजाइन के साथ-साथ खेल सामग्री के क्षेत्र में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।' अभी तक के बजट में खेल सामग्री क्षेत्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। खेल मंत्रालय ने इस आवंटन का स्वागत किया और कहा कि खेल सामग्री उद्योग के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी।

खेलो इंडिया मिशन

सीतारमण ने अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने के प्रस्ताव रखा जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि यह मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान के लिए सभी आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था। सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा, 'खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।'

22 साल के कार्लोस अल्काराज बने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन

फाइनल में 38 साल के जोकोविच को हराया

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना स्पेन के कार्लोस अल्काराज से हुआ। एक तरफ युवा जोश और दूसरी तरफ अनुभव था, लेकिन अल्काराज का युवा जोश जोकोविच के अनुभव पर भारी पड़ा। पहला सेट जोकोविच ने 6-2 से अपने नाम किया था। पहले सेट में जोकोविच ने सर्विस और फॉर हेंड का जबरदस्त दम दिखाया। इसके बाद दूसरे सेट में अल्काराज ने जबरदस्त वापसी की और 6-2 से सेट अपने नाम किया। फिर तीसरे सेट में जोकोविच थके हुए नजर आए और इसका फायदा अल्काराज ने उठाया और 6-3 से जीत हासिल की।

अल्काराज के लिए बड़ा मौका

अल्काराज ने अब तक सात ग्रैंडस्लैम जीते हैं। यह उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। अल्काराज पिछले साल भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन सिनर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस बार सिनर को जोकोविच सेमीफाइनल में हराकर बाहर कर चुके थे, जबकि अल्काराज ने सेमीफाइनल में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था और अपना दम दिखाया था। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक माना गया है। अल्काराज के 7 ग्रैंडस्लैम खिताबों में 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब: 2026, 2 फ्रेंच ओपन खिताब: 2024, 2025, 2 विंबलडन खिताब: 2023, 2024 और 2 यूएस ओपन: 2022, 2025 हैं।

जूनियर पुरुष स्कीट टी2 ट्रायल्स में पंजाब का क्लीन स्वीप

नई दिल्ली। शॉटगन राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स 1 एवं 2 के अंतर्गत जूनियर पुरुष स्कीट टी2 फाइनल में पंजाब के निशानेबाजों ने पोडियम पर कब्जा जमा लिया। हरविराज सिंह, हरजीज सिंह अटवाल और गुरफतेह सिंह संधू ने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कब्जा किया। सीनियर वर्ग में अनंतजीत सिंह नरूका ने 36 का परफेक्ट स्कोर कर ट्रायल 2 फाइनल जीता जबकि महिला वर्ग में यशस्वी राठौड़ ने केवल एक निशाना चूकते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। सीनियर पुरुष फाइनल में नरूका ने सभी 36 निशाने साधे। ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया ने भी 34वें टारगेट तक परफेक्ट स्कोर रखा, लेकिन 35/36 के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अभय सिंह सेखों ने 30 निशानों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

देविका सिहाग ने बढ़ाया भारत का मान

थाईलैंड मास्टर्स

एजेंसी । बैंकॉक

हरियाणा की 20 वर्षीय शटलर देविका सिहाग ने बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स (सुपर 300) का खिताब जीतकर भारतीय बैडमिंटन इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस जीत के साथ ही देविका, दिग्गज साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल मुकाबले में देविका का दबदबा इस कदर था कि जब उनकी प्रतिद्वंद्वी, मलेशिया की गोह जिन वेई ने हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैच छोड़ा, तब देविका 21-8, 6-3 से मजबूत बढ़त बनाए हुए थीं।

मैदान पर दबदबा और तकनीकी श्रेष्ठता

फाइनल मैच में देविका ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और दमदार रिटर्न व सटीक स्ट्रोक्स के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। उन्होंने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए क्रॉस कोर्ट स्मैश और कुशलता से लगाए गए ड्रॉप शॉट्स के जरिए गोह को कोर्ट पर खूब दौड़ाया। इंटरवल तक 11-4 की बढ़त हासिल करने के बाद देविका ने अपनी लय बरकरार रखी और बैकहैंड क्रॉस शॉट के साथ पहला गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में भी जब वे 6-3 से आगे थीं, तब मलेशियाई खिलाड़ी की शारीरिक परेशानी ने देविका की जीत पर मुहर लगा दी।

बॉलीवुड

'मर्दानी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दमदार पकड़

यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी रानी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरे दिन कमाई में करीब 50 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। फिल्म ने रिलीज़ के महज़ दो दिनों में 10 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन कर लिया है।

शनिवार को फिल्म ने लगभग 6 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि ओपनिंग डे पर यह आंकड़ा 4 करोड़ रुपये रहा था। मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और सकारात्मक समीक्षाओं के चलते रविवार को फिल्म के कलेक्शन में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। रिलीज़ के पहले दिन ही 'मर्दानी 3' ने फ्रेंचाइज़ी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कर ली थी। इसके साथ ही यह रानी मुखर्जी के करियर की सबसे बड़ी सोलो ओपनर फिल्म बनकर उभरी है। महिला-प्रधान फिल्मों की श्रेणी में यह ओपनिंग एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषय पर आधारित यह थ्रिलर फिल्म कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा पसंद करने वाले दर्शकों के बीच खासा प्रभाव छोड़ रही है। समीक्षकों ने भी फिल्म की कहानी, प्रस्तुति और रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय की सराहना की है। फिल्म को संतुलित और रणनीतिक रिलीज़ मॉडल के तहत सिनेमाघरों में उतारा गया है, जिसमें मेट्रो शहरों और शहरी केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। फ्रंट-लोडेड कलेक्शन के बजाय लंबी अवधि की कमाई पर फोकस के बावजूद दूसरे दिन की यह बढ़त फिल्म की मजबूत दर्शक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। महामारी के बाद के दौर में, जब हिंदी थ्रिलर जॉनर को सिनेमाघरों में संघर्ष करना पड़ा है, 'मर्दानी 3' ने खुद को उन चुनिंदा फिल्मों की सूची में शामिल कर लिया है, जिन्होंने थिएटर में ठोस पकड़ बनाई है।

राम चरण के घर गूंजी किलकारियां, उपासना ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला के घर खुशियों की दोगुनी दस्तक आई है। 31 जनवरी, 2026 को इस जोड़े ने जुड़वा बच्चों एक बेटे और एक बेटी का स्वागत किया। इस बड़ी खबर की पुष्टि खुद राम चरण के पिता और साउथ के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर की, जिससे परिवार और प्रशंसकों में जश्न का माहौल बना हुआ है। चिरंजीवी ने इस खुशी के पल को दैवीय आशीर्वाद बताते हुए लिखा, ₹अत्यधिक खुशी और आभार के साथ हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राम चरण-उपासना को जुड़वा बच्चों एक बेटे और एक बेटी, का आशीर्वाद मिला है। मां और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। दादा-दादी के रूप में इन नन्हें बच्चों का स्वागत करना हमारे लिए आनंद और दैवीय आशीर्वाद का क्षण है। हम सभी के प्रार्थनाओं, प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से आभारी हैं। चिरंजीवी और सुरेखा। राम चरण और उपासना की पहले भी खुशी भरी खबर रही है। साल 2023

में उनके घर बेटी क्लिन कारा का जन्म हुआ था। अब 2026 में जुड़वा बच्चों के जन्म के साथ उनका परिवार और भी पूरा हुआ है। इससे पहले, उपासना और राम चरण ने पिछले साल दिवाली के मौके पर अपने प्रशंसकों को बताया था कि वे फिर माता-पिता बनने वाले हैं। राम-उपासना की प्रेम कहानी भी फिल्मी अंदाज़ की है, दोनों की मुलाकात करीब एक दशक पहले एक स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी, जो दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने जून 2012 में हैदराबाद में एक भव्य समारोह में शादी की थी। खुशी के बीच राम चरण काम के मोर्चे पर भी व्यस्त हैं।

धनुष की 55वीं फिल्म का एलान

धनुष ने हाल ही में अपनी 55वीं फिल्म का एलान किया है, जिसका अस्थाई नाम 'डी55' है। निर्माताओं ने स्टार कास्ट की घोषणा भी कर दी है। निर्देशक राजकुमार पेरियासामी की अगली फिल्म में धनुष के साथ मुख्य भूमिका में यह अभिनेत्री पहली बार नजर आएंगी। राजकुमार पेरियासामी पहले 'अमरन' फिल्म बना चुके हैं। धनुष की आगामी फिल्म का अस्थाई नाम 'D55' है। यह अस्थाई नाम इसलिए 'D55' रखा गया है क्योंकि यह धनुष की 55वीं फिल्म हैं। इस फिल्म में उनके साथ पहली बार मुख्य अभिनेत्री के रूप में श्रीलीला नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरियासामी करेंगे। धनुष और श्रीलीला पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं।

'बैटल ऑफ...' के सीन पर ट्रोलर्स को जवाब

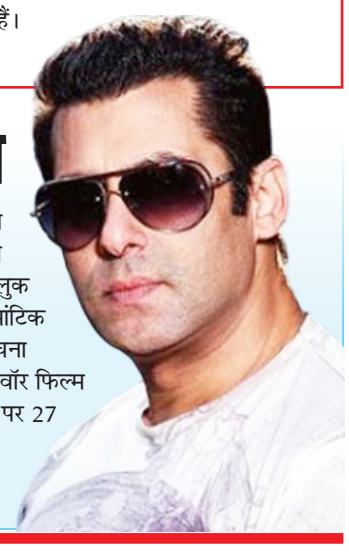

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी आगामी वॉर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में दिखाए गए लुक पर चल रहे ट्रोलिंग पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने सलमान के एक छोटे से सीन को "रोमांटिक ग्लांस" बताकर आलोचना की थी, लेकिन सलमान ने इसे मजाक में उड़ा दिया। साथ ही कहा कि यह भाव किसी रोमांस का नहीं, बल्कि एक कर्नल की गंभीर सोच का है। सलमान ने हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मैच के दौरान टीजर का वह सीन दोबारा किया और कहा, "अब किसी को ये रोमांटिक लुक लगता है, लेकिन मैं फिल्म में कर्नल हूं भैया, यह एक कर्नल का लुक है जो टीम और जवानों को हौसला देता है।" उन्होंने यह भी मजाक में कहा कि वह चाहें तो वही लुक और भी दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई "रोमांटिक मतलब" नहीं है और यह नाराजगी या आलोचना उन्हें प्रभावित नहीं करती। सलमान खान की वॉर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर उनके बर्थडे पर 27 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। फिल्म का पहला ट्रैक 'मातृभूमि' 24 जनवरी को ही लॉन्च हो चुका है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया 'धुरंधर' रक्षा बजट

- राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार का फोकस, रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी
- रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 7,84,678 करोड़ का आवंटन
- सरकार ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए भी भारी-भरकम राशि आवंटित की

पिछले पांच सालों के दौरान रक्षा बजट

2026-27 7.85 लाख करोड़
2025-26 6.81 लाख करोड़
2024-25 6,22 लाख करोड़
2023-24 5.94 लाख करोड़
20122-23 5.25 लाख करोड़

एजेंसी । नई दिल्ली

रक्षा बजट पर पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर की छाप स्पष्ट नजर आ रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में रिकॉर्ड एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कमर कस चुकी है। रविवार को पेश आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 7,84,678 करोड़ का आवंटन किया गया है। यदि इसकी तुलना पिछले यानी चालू वित्त वर्ष के बजट से करें तो 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा बजट 6,81,210 करोड़ है। पहली बार रिकॉर्ड करीब 1.03 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि रक्षा के मद में हुई है।

ऑपरेशन सिंदूर का असर

बता दें कि पिछली बढ़ोतरी सिर्फ नौ फीसदी की हुई थी। इस बार 15 फीसदी की वृद्धि के बावजूद रक्षा बजट जीडीपी के दो फीसदी ही है। वैसे चीन भी रक्षा पर दो प्रतिशत के करीब ही खर्च करता है, लेकिन उसकी जीडीपी का आकार बहुत बड़ा है। रक्षा बजट का सबसे महत्वपूर्ण भाग सेनाओं के आधुनिकीकरण का बजट होता है। वर्ष 2026-27 के लिए 2,19,306 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछली बार 1,80,000 करोड़ का आवंटन हुआ था। हालांकि संशोधित बजट अनुमान में यह राशि बढ़कर 1,86,454 करोड़ तक पहुंच गई थी। यानी जितनी राशि आवंटित हुई थी, खर्च उससे कहीं ज्यादा हुआ। इसकी एक प्रमुख वजह ऑपरेशन सिंदूर भी रहा है, जिसके बाद सरकार ने रक्षा तैयारियों को तेज किया है। बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर आवंटन बढ़ाया गया है।

आधुनिकीकरण के मद में 22 फीसदी वृद्धि

यदि रक्षा आधुनिकीकरण के मद की बात करें तो उसमें 22 फीसदी वृद्धि हुई है। आधुनिकीकरण के 75 फीसदी यानी 1.39 लाख करोड़ स्वदेशी खरीद पर खर्च होगा। राजस्व व्यय के लिए 5,53,668 करोड़ रक्षा राजस्व व्यय के लिए 5,53,668 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह राशि रक्षा सेवाओं के संचालन के लिए होती है। मौजूदा बजट में इस मद में 4.91 लाख रुपये आवंटित हुए थे। इसमें करीब 13 फीसदी की बढ़ोत्तरी है। भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन की राशि के लिए आवंटन में भी बढ़ोतरी हुई है। इस मद में 1,71,338 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मौजूदा वर्ष के दौरान यह आवंटन 1.6 लाख करोड़ के करीब है। पेंशन की राशि में साल दर साल बढ़ोत्तरी हो रही है।

हर साल नया अंदाज......

साल 2019 | साल 2020 | साल 2021 | साल 2022 | साल 2023 | 2024 अंतरिम | साल 2024 | साल 2025 | साल 2026

इनकम टैक्स स्लैब जस का तस

रिवाइज्ड रिटर्न अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक भरें

विदेश पैसे भेजने पर अब 2% टैक्स

एजेंसी । नई दिल्ली

बजट 2026 में आम करदाताओं की सबसे ज्यादा नजर इनकम टैक्स स्लैब पर टिकी हुई थी। हालांकि, इस बार वित्त मंत्री ने आयकर की दरों या स्लैब में कोई बड़ा बदलाव करने का ऐलान नहीं किया। लेकिन राहत की बात यह रही कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब करदाता 31 मार्च तक नाममात्र शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे नौकरीपेशा और छोटे करदाताओं को काफी सहूलियत मिलेगी, जो तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से समय पर रिटर्न नहीं भर पाते। अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) की बात करें, तो इसमें स्लैब पहले जैसे ही रखे गए हैं। सालाना 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लागू रहेगा। इस व्यवस्था में छूट और कटौतियों (जैसे HRA, 80C, 80D) का फायदा मिलता है, इसलिए कई करदाता अभी भी इसे पसंद करते हैं। वहीं नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में ज्यादा स्लैब हैं और टैक्स दरें चरणबद्ध तरीके से बढ़ती हैं। 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख तक 5 फीसदी, 8 से 12 लाख तक 10 फीसदी, 12 से 16 लाख तक 15 फीसदी, 16 से 20 लाख तक 20 फीसदी और 20 से 24 लाख तक 25 फीसदी टैक्स लगेगा। 24 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए आसान मानी जाती है जो ज्यादा कटौतियों का दावा नहीं करते। कुल मिलाकर, बजट 2026 में टैक्स स्लैब भले न बदले हों, लेकिन प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश जरूर दिखाई दी।

मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर राहत

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज को अब पूरी तरह आयकर से मुक्त किया जाएगा। साथ ही, इस पर टीडीएस की कटौती भी नहीं की जाएगी।

विदेश रुपए भेजने पर कम टैक्स

पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर अब कम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लगेगा। सरकार ने इसे 5% से घटाकर 2% करने का फैसला किया है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5% और 20% के TCS रेट को घटाकर 2% किया गया है।

मैनपावर सर्विसेज पर टीडीएस स्पष्ट

मैनपावर सप्लाई सेवाओं को अब स्पष्ट रूप से कॉन्ट्रैक्टर को किए जाने वाले भुगतान के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1% या 2% ही लागू होगी, जिससे भ्रम की स्थिति खत्म होगी।

छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम

छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के जरिए कम या शून्य टीडीएस कटौती का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

Form 15G / 15H की प्रक्रिया होगी आसान

एक से ज्यादा कंपनियों में निवेश करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए डिपॉजिटरी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह निवेशक से Form 15G या Form 15H स्वीकार कर सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचा सके।

रिटर्न संशोधन और फाइलिंग की समयसीमा में बदलाव

सरकार ने आयकर रिटर्न संशोधित करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है, हालांकि इसके लिए मामूली शुल्क देना होगा। इसके अलावा, रिटर्न फाइल करने की समयसीमा को भी चरणबद्ध किया जाएगा:

एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद पर टीडीएस प्रक्रिया आसान

गैर-निवासी यानी NRI से अचल संपत्ति खरीदने पर अब टीडीएस जमा करने के लिए खरीदार को TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया अब PAN आधारित चालान के जरिए पूरी की जा सकेगी।

फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग करना महंगा

सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। ऑप्शंस पर भी STT को बढ़ाकर 0.15% किया गया है। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा।

विदेशी संपत्ति खुलासे के लिए विशेष योजना

छोटे करदाताओं जैसे छात्रों, युवा पेशेवरों, टेक कर्मचारियों और स्थानांतरित एनआरआई की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक बार की 6 महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत तय सीमा से कम आय या संपत्ति का खुलासा किया जा सकेगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स लगेगा

अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब केवल उन्हीं निवेशको टैक्स-फ्री होने का फायदा मिलेगा जिन्होंने RBI से बॉन्ड खरीदे और उसे पूरी अवधि तक रखा। पहले SGB पर ब्याज के अलावा जो भी फायदा निवेशकों को होता था, वह मैच्योरिटी

रेलवे को मेगा बूस्ट!

एजेंसी । नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन व कोच की खरीद के साथ-साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन, पिछले वर्ष से 10.25% अधिक।
- रेलवे को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
- मुंबई-पुणे और चेन्नई-बेंगलुरु समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा

रेलवे की कुल कमाई 3,85,733 .33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान

बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733 .33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186 .01 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547 .32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, 'रेलवे की कमाई इतनी कम है कि वह परिसंपत्ति बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं।'

भारत को जोड़ने वाला मार्ग बनेगा

रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने देश के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने के लिए नए कॉरिडोर बनाने की तैयारी की है। इसमें मुंबई-पुणे (कॉरिडोर)महाराष्ट्र के दो बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ेगा। दिल्ली-वाराणसी उत्तर भारत का प्रमुख कनेक्टिविटी लिंक है, फिर वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग बनेगा। पुणे-हैदराबाद आईटी और औद्योगिक हब के बीच तेज रफ्तार मुहैया कराएगा। इसके अलावा हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दक्षिण भारत में तेज रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगे। नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से दूसरे रेलमार्गों पर मेल-एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति 55 किमी प्रतिघंटा से बढ़कर 60-70 प्रतिघंटा हो जाएगी। वहीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन 90-95 किमी प्रतिघंटा से फर्राटा भरेगी। भविष्य में इन ट्रेन को अधिकतम रफ्तार 160-180 किमी प्रतिघंटा दौड़ने की है।

नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये

बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहरीकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, सिग्नलिंग व दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024-25 में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

रफ़्तार का नया युग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में पेश आम बजट 2026-27 में वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस-स्लीपर, अमृत भारत आदि सेमी हाई स्पीड ट्रेन को फुल स्पीड से दौड़ने के लिए सात नए हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की। इसके साथ ही भारतीय रेल में नए रफ्तार युग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि उक्त कॉरिडोर पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन समय पर चलेंगी। वहीं, इससे मेल-एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति 60-70 फीसदी तक बढ़ जाएगी। इससे इंजन-कोच-वैगन (रोलिंग स्टॉक) का उत्पादन, ट्रैक नवीनीकरण, नई लाइनें, आमान परिवर्तन, लाइनों का दोहरीकरण तेजी से किया जा सकेगा। आम बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए निर्मला सीतारमण ने रेल नेटवर्क के कायाकल्प के लिए सात नए हाई-स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर का प्रावधान किया है। यह कदम न केवल शहरों के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि भारतीय रेल की औसत गति में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।